MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Indian Railway Board Act, 1905."

The motion was adopted.

SHRI BHOGENDRA JHA: Sir, I introduce the Bill.

UNIVERSAL COMPULSORY PRIMARY EDUCATION BILL*

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for universal, free and compulsory primary education in India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for universal, free and compulsory primary education in India."

The motion was adopted.

SHRI BHOGENDRA JHA: Sir, I introduce the Bill.

15.50 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Sections* 3, 6*B*, *etc.*) by Shri Mool Chand Daga—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Mool Chand Daga on 18th September, 1981 namely:—

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The time allotted was 2 hours.

We have already taken only two minutes.

We have got a balance of 1 hour and 58 minutes.

MR. Daga was on his legs. He may continue his speech.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार का सब से बड़ा लोकतन्त्र प्रणाली में विश्वास रखने वाला देश भारत है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस देश की सब से बड़ी सर्वोच्च संस्था का सदस्य हूं । यह मेरा सौभाग्य है कि देश के निष्ठावान, कर्मनिष्ठ तथा सेवाभावी लोगों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, जिन्होंने अपनी जिन्दगी को, जिनमें उपाध्यक्ष महोदय आप भी शामिल हैं, देश के प्रति कर्तव्यों की वेदी पर अपने स्वार्थों की बलि दे दी है । जिन्होंने देश के प्रति अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया है । अगर इन लोगों का काम देखा जाय, पहले उधर जो बैठने वाले लोग हैं उनको ले लीजिये, चाहे लोक दल के माननीय सदस्य हों, या किसी और दल के माननीय सदस्य हों, कभी किसानों की समस्याओं को लेकर झूझते हैं, कभी हमारे मजदूर नेता शास्त्री जी मजदूरों की समस्याओं पर अपनी आवाज बुलन्द करते हैं और कभी हम लोग देश के विभिन्न मामलों पर अपनी बात, चाहे विदेशी नीति हो, देश की एकता को कायम रखने वाली बात हो, अपने विचार यहां प्रकट करते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं—इस सदन का हर सदस्य हर वक्त जागरूक और सतर्क रहना चाहता है और रहता है । एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य जज 196 दिन काम किये बिना भी चल सकते हैं, एक सरकारी कर्मचारी जो दिन में 8 घन्टे काम करता है, यदि मन से नहीं करता है तो भी उसके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है हम लोग 18-19 घन्टे लगातार काम करते हैं—इस सम्बन्ध में हमारे स्पीकर महोदय ने अपने भाषण में एक बार कहा था

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-11-1981.

[श्री मूलचन्द डागा]

Functions of Legislators inside and outside the Legislature: 28 August 1981.

उन्होंने बतलाया था कि एक मेम्बर को क्या-क्या काम करना पड़ता है, मैं उस रेलेवेन्ट पोर्शन को पढ़ना चाहता हूं--

"Friends, whether it is inside the House or outside it, a legislator is a bridge between the people and the Government. It is he to whom the common folk turn to for help; and it is he who has often to intercede on their behalf with the public functionaries for finding solutions to some of their day to day problems. To my mind, nothing can be more gratifying or fulfilling to a legislator than the satisfaction that he has been able to constructively contribute to the welfare of the community around him. But the people make all kinds of demands on him—from admissions to schools and colleges, postings and transfers etc. to fertilizers, water supply and so on. Some of the demands made on the legislator, of course, place him in an unenviable situation."

"But he has to tackle the problems as best as he can and pursue them systematically with the concerned authorities. Even as he brings to the attention of Government the grievances, urges and expectations of the people, he must also serve as a conduit of information to the people and keep them constantly informed about the various policies and programmes of the Government and the happenings in the legislature."

लाखों, करोड़ों लोगों की बात करने वाला एक सदस्य, कितना बड़ा यह मुल्क और उसकी बात करने का मेम्बर का अधिकार और कितना उसको पैसा मिलता है। आज केरल में कोई घटना घटती है, तो मेरे दिल को चोट पहुंचती है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो मेरे मन में दुःख पैदा होता है। एक चुना हुआ सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के दुखों में दुखी और सुख में सुखी होता है। उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा उसका उत्तरदायित्व है, यह आप जानते हैं लेकिन मैं ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी भूमिका अच्छी बनी रहे, यह हम चाहते हैं। हमारे मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स और स्टेट होम मिनिस्टर, श्री वेंकटसुब्बया, यहां पर बैठे हुए हैं। उनके और जनता के बीच में हम एक ब्रिज बनना चाहते हैं। हमारा यह काम है कि हम सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करें और आपके सामने जनता की बातें रखें। इस सम्बन्ध में हमने एक बिल पेश किया था 1954 में और 1954 के बाद आज मैं यह बिल पेश कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि हम काम करें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और एक अच्छी भूमिका निभाएं, स्वच्छ और स्वस्थ भूमिका निभाएं। किस प्रकार से हम भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका निभाने का तरीका क्या है। एक तरीका है, जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं :

"Few can afford to work for love alone. As Sir Winsten Churchill, one of the greatest parliamentarians of all, said to another context: 'Give us the tools, and we'll finish the job."

चर्चिल ने यह कहा था कि हमें अपने साधन दे दो, हम अपने काम के लिए स्वस्थ भूमिका निभाएंगे। यह एक मानी हुई बात है कि अगर हिन्दुस्तान के किसी एक हिस्से में कोई घटना होती है, तो हिन्दुस्तान के लोगों का जो नुमायंदा संसद सदस्य है, उस के पास यदि जाने के लिए साधन हों, अगर वह कहीं जाना चाहे, तो जा न सकता हो, वह पूरे अखबारों का कन्ट्रीब्यूशन न कर सकता हो, उसके रहने के लिए पूरी सुविधाएं न हों, तो किस प्रकार से वह अपना काम कर सकता है। कैसे हम काम कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ब्रिटेन में वहां के संसद सदस्यों को बहुत ज्यादा मिलता है और जो वहां मिलता है, वह हमें मिले लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां के संसद् सदस्य को क्या मिलता है।

"Members of Parliament enjoy the run of nine bars and a diverse

choice of restaurants, as well as some of the wittiest conversation in the kingdom, and they are actually paid for belonging. They receive a basic salary of £6,270 a year, plus a subsistence allowance of £2,534 and a secretarial allowance of £3,687, making a grand total of £12,491."

2 लाख 15 हजार रुपये उसे मिलता है और मुझे मिलता है केवल 30 हजार रुपया। जो देश बड़ा, समस्याएं बड़ी, काम बड़ा, उसमें कोई सेक्रेटरी नहीं, कुछ है तो हाथ है, इन्हीं से जितना चाहो काम कर लो।

16 hrs.

एक माननीय सदस्य : हमें तीस हजार कहां, 18 हजार मिलते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: 18 हजार होंगे।

"Top of the league are West German deputies with a salary of £22,700 and allowances worth a further £13,600. M.Ps. in Denmark, France and Holland also get at least three times as much as their British counterparts."

इन देशों में तीन गुना मिलता है। लेकिन मैं इन देशों की बात नहीं करता क्योंकि हमारे यहां कई ऐसे लोग भी हैं जो अलमारी में कोकशास्त्र रखते हैं और हाथ में रामायण रखते हैं। बड़े-बड़े उपदेश और भाषण देते हैं। लेकिन मैंने अपनी सारी जिन्दगी में किसी को भी नहीं देखा कि बिल पास होने के बाद, एमोल्युमेंट्स बढ़ने के बाद किसी ने भी उनको छोड़ दिया हो। यह हमारी हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, आप गौर करें। इस में लिखा है—

"India's M.Ps. are among the lowest paid. They receive Rs. 500 a month—equivalent to under £33—plus a daily allowance of about £3 when Parliament is in session."

हमको 33 पाउन्ड मिलते हैं। अब रावत जी बताएं जो कि जवानी लिये बैठे हैं। क्या आप अपनी जिन्दगी इस तरह से चलाना चाहते हैं? क्या आप कुछ काम करना चाहते हैं? आप दुनिया में किस तरह से रहना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि अर्जेंटीनी में 84 हजार डालर, आस्ट्रेलिया में 21 हजार 552 डालर, केनाडा में 18 हजार डालर, फ्रांस में 21 हजार 640 डालर, और हमारे देश के अन्दर 805 डालर मिलते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can also mention the per capita income of these countries and that of India.

SHRI MOOL CHAND DAGA: I will say that also and do justice to the subject. I will give those details in my reply.

अब मैं आपको डवलपिंग कन्ट्रीज के बारे में बताता हूं। मलेशिया डवलपिंग कन्ट्री है वहां 5 हजार 1 सौ डालर मिलता है और हमारे यहां 805 डालर मिलता है। एक डवलपिंग कन्ट्री श्रीलंका है उसमें 2 हजार डालर मिलते हैं। पाकिस्तान में 1 हजार 800 डालर मिलते हैं। अब आप बताइये कि कहां मलेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान और कहां हम।

अगर आप कहें कि डवलप्ड कट्रीज की मैं बात न करूं तो आप डवलपिंग कन्ट्रीज को ही देखिये कि उनमें क्या मिलता है और मिलने के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। हमारे यहां एक किताब है—"पार्लियामेन्ट्स आफ दि वर्ल्ड"—उसमें दिया हुआ है कि क्या कंवेंस का मिलता है, क्या और फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारे देश के अंदर एक सेक्रेटरी वी. आई. पी. के नीचे हम को रखा जाता है। और जो मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स . . .।

AN HON. MEMBER: They are also not well-paid.

श्री मूलचन्द डागा : यह मैंने कब कहा?

From the Reference I quote:

"The Ministry of Finance has been contacted on phone and they have informed us that the Sceretary to the Government of India draws a salary of Rs. 3,500/- besides additional allowances of Rs. 600/-."

[श्री मूलचन्द डागा]

हमारी तन्ख्वाह तो 500 रुपये है ।

> "And a compensatory allowance of Rs. 75/-. Then he gets so many facilities—free bangalow, house, car."

पता नहीं आप हमसे क्या चाहते हैं ? अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, आप देखिए---सिक्किम में 800 रुपये प्रति माह मिलता है और डेली अलाउंस 55 रुपये मिलता है । नागालैण्ड में 750 रुपये प्रति माह मिलता है । महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में तो मजे ही मजे हैं । कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस 500 रुपये । परसनल असिस्टेंट । एक सेक्रेटरी जब आता है तो उसके पीछे डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, क्लर्क, सब दौड़े आते हैं, लेकिन एम.पी. तो खुद ही दौड़ता है ।

यह हालत है । आप देखिए कि 1954 में एक बिल इंट्रोडयूज किया गया था और उसके बाद 1981 के अंत में. . .इन्कम-टैक्स 12000 पर लगता है, आप हमको एक हजार रुपया प्रतिमाह दे दीजिए । समझदार लोग कहेंगे कि बहुत कम मांगता है, मूर्ख है । मैं कहता हूं कि स्टेट्स से कंपेरीजन कर लीजिए । महाराष्ट्र में देखिये, फ्री हाउस, नो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, लेकिन यहां पर तो सुंदरलाल चौधरी से 170 रुपया महीना ले लते हैं । फोन का ही कितना खर्च आ जाता है, इसको भी आप देखें । सारे सदस्यों के दस्तखत मेरे पास मौजूद हैं इस के पक्ष में और सरकार को हमारी मांग को मंजूर कर ही लेना चाहिये । आप देखें कि हरियाणा में धर्म पत्नी को पति और धर्मपत्नी पति को साथ ले जा कर सारा भारत घूम सकते हैं और फर्स्ट क्लास में घूम सकते हैं, महाराष्ट्र वाले घूम सकते हैं लेकिन हमारी क्या हालत है । गाड़ी इतनी लम्बी होती है, डिब्बे इतने अधिक होते हैं कि धर्म पत्नी कहीं बैठती है और पति कहीं और बैठता है, एक कहीं रह जाता है और दूसरा कहीं और सामान कुली ले जाता है । हम चाहते हैं कि हम ईमानदारी से, सही तरीके से जिन्दगी जियें । राजनीति एक सेवा का विषय है । नैतिकता गिरनी नहीं चाहिये । हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके, इसका प्रबन्ध होना चाहिए । इसलिए अगर आप सही काम हम से करवाना चाहते हैं तो एक काम आपको करना होगा । हमको आपको सक्षम बनाना होगा । दिल्ली में शाम का खाना अगर खाने हम चले जाएं तो जो डेली एलाउंस मिलता है वह उसी में खत्म हो जाता है । राज्यों में क्या मिलता है इसको भी आप देखें । राजस्थान में 51 रुपये देते हैं और हमारे यहां भी 51 रुपये । हम ईजीली एप्रोचेबल हैं, मंत्री नहीं। मंत्री के यहां कोई जाता है तो उसको संतरी बाहर से ही कह देता है या कह सकता है कि मंत्री साहब बाथ रूम में हैं । हम कहां जाएं । बाथ रूम में भी लोग हमारे पास आ जाते हैं । हमारे हजारों मालिक हैं । मुसीबत में पली हुई हस्तियां ही बड़ी हस्तियां बनती हैं । कभी कभी सरकारी कर्मचारी जो ऊंचे पदों पर बैठते हैं वे हमारी स्थिति को समझते हैं । कम्युनिकेशन का अगर कोई मंत्री है तो उसे संचार के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है । होम का है तो होम के बारे में रखनी पड़ती है, रेलवे का है तो उसकी । लेकिन हम लोगों को इकोनोमिक्स की, कामर्स की, टैक्नालाजी की, साइंस की गर्ज कि दुनियां के नीचे जितने विषय हैं, जिन को हम नहीं जानते हैं, उन सब को हम को जानना पड़ता है । गाड़ियों में लुटेरों को भी हम पकड़ते हैं । एक मंत्री के वास्ते एक या दो सबजेक्ट्स की मास्टरी जरूरी है । लेकिन हम लोगों को सारे सबजेक्ट्स पर मास्टरी करनी पड़ती है । किस प्रकार से काम करें, समझ में नहीं आता । अखबार घर में मंगाये तो उसके भी पैसे बढ़ गये, इंडिया टूडे मंगाइये या और मैगजीन मंगाओ तो 70, 80 रु. इन्हीं का खर्चा हो जाता है और दो घर चलाने पड़ते हैं हमें, एक यहां और दूसरे अपने क्षेत्र में । अगर बच्चे बाहर पढ़ते हों तो और खर्चा करना पड़ता है । क्या हमारी स्थिति होती है । जब हम यह बात करते हैं तो लोग आदर्श की बात

करते हैं । आदर्श की बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी हैं । सरकार हमें एक सेक्रेटरी दे दे, फुलफ्लेजड काम करने वाला एक स्टेनो दे दीजिए । अभी 750, 800 रु. महीना वह ले जाता है और डाक पर भी हमें 500, 600 रु. महीना खर्च करना पड़ता है । मैंने एक सिलसिला चलाया कि भाई जवाब मंगाना हो तो जवाबी कार्ड भेज दो । जब मीटिंग में गया तो वहां पढ़ कर लोगों ने सुना दिया पब्लिक मीटिंग में । मैंने कहा भाई माफी मांगता हूं । तुम्को यह कहना भी गुनाह है । अगर कोई कारस्पोंडेंट आ जाय या श्री सुलेमान सेत साहब आ जायें तो चाय भी पिलानी पड़ेगी । तो आप चाहते क्या हैं एम. पी. से ? अगर आदर्श वाद ही करना है तो माला ले कर लंगोट पहन लेना पड़ेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माला भी नहीं मिलेगी ।

श्री मूल चन्द डागा : आप जैसे लोगों को तो मिलेगी भी नहीं कि बाहर से कुछ और अन्दर से कुछ । ऐसों को माला मिलनी भी नहीं चाहिये, माला का भी अपमान हो जायगा ।

यह बड़ा गम्भीर विषय है, और माननीय वेंकटसुब्बय्या जी काबिल मंत्री हैं, 30 साल से वह पार्लियामेंट में हैं, उनकी बात पर हमें पूरा विश्वास है, हमारी बात को पूरी तरह से कैबिनेट के सामने रखेंगे । और डिप्टी स्पीकर साहब भी बाहर जा कर बात करेंगे कि किस प्रकार से मेम्बरों ने अपनी बातें कहीं और उसको आप ज्यादा ठीक रूप से समझ कर के कहिये । अगर आप हमें रुपया नहीं देते तो साधन दे दीजिये, स्टेनो दे दीजिये, कन्वेयंस दे दीजिये । माननीय वृद्धि चन्द जैन का निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरा हरियाणा उसमें आ जाय । 66,000 वर्ग किलोमीटर । माननीय नामग्याल जी का लद्दाख क्षेत्र 97,000 वर्ग किलोमीटर है । साल भर भी पैदल घूमें तो नहीं घूम सकते । सुल्तानपुरी जी का भी पहाड़ी क्षेत्र है जहां गाड़ी नहीं जाती है । कितने खच्चर मर गये होंगे इनके बैठने से । कितनी लम्बी यात्रा हमको करनी पड़ती है । अगर हम अपने डिस्ट्रीक्ट में जायें तो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, पैट्रोल बहुत मंहगा । 200 रुपये रोज का कम-से कम पैट्रोल चाहिये । एक दिन की यात्रा में भी बहुत खर्चा हो जाता है । अगर कई दिन घूमना पड़ जाये तो महीने भर की तनख्वाह तो उसमें ही चली जाती है ।

चुनाव के समय जो हमें करना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत सारे ऑब्लीगेशन्स हैं । जो बात मैं कह रहा हूं, उसमें यह था--

"1. The spouse of a Member should be given a free First Class Railway Pass to enable her to travel anywhere and any time.

2. The spouse of a Member should be allowed to travel by air once during each Session of Parliament.

3. Within the present financial limits permitted under the law, the bills of trunk calls, phonograms and the bills of the Member's one private telephone should be covered.

4. Road mileage should be increased to Rs. 2.50 per kilometre.

5. Daily allowance should be increased to Rs 101/- per day.

6. Salary should be increased to Rs. 1,000/- per month.

7. Wnen the spouse does not travel with the Member, the companion should be permitted to travel by First Class with the Member.

And this was signed by so many members."

MR. DEPUTY-SPEAKER: I agree with you on one point. The spouse should always travel along with the Member, wherever they go.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): May I ask Shri Daga one question? Shri Daga has so far not referred to one thing. Mr. Daga, you remember, on the pass of the Member,

[Shri Bapusaheb Parulekar]

there is the photograph of the Member but on the spouse's pass there is no photograph. You have to comment on that.

श्री मूलचन्द डागा : यह तरकीब आपको मालूम हो गई है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the spouse is allowed to travel along with the M.P., wherever he goes, then the Member need not have any complaint.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Here is a book, "*Honourable Members*" and I want to read one or two passages from it.

क्योंकि जो हमारे शास्त्रीजी की बात है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यह बात सब दुनिया जानती है । लेकिन यह जानकर खुश होंगे कि किस प्रकार का मेम्बर का काम होता है ।

पहले जो इन्होंने बात कही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, फिर आपकी सेवा में बात कहूंगा ।

Here, Christopher Hollis, an ex-Member, has described "how great is the burden of work that must be carried by an Honourable Member." Then he described "Parliamentary life as a ceaseless round of activity which necessitates the sacrifice of home life, recreations and cultural activities."

Mr. Arakal, do you remember the complaints of your wife? (*Interruptions*).

He has no home life. He comes here and says something. He has to prepare his speech. He cannot attend to anything at hone. No home work. No domestic duties.

उस पर उन्होंने कुछ बताया कि किस प्रकर से काम करना चाहिये, उन्होंने कहा कि इम्पासिबल ।

Again, it is mentioned here,

"It is alleged that if Members were better paid, a less desirable type of person would be attracted to the Commons whose motive would be that of personal gain rather than political principle or the desire to serve the community. Alternatively, it is urged that the House would become composed of professional politicians, devoid of outside interests and the wide range of experience which is now a characteristic of the Commons."

"These views, widely and sincerely held, are mistaken. If a Member's pay were such that a reasonable standard of living was assured without the need to seek additional income, many more men and women of high ability, seriously concerned with the public issues of our time, would come forward as potential candidates. Why should an increase in the supply of candidates cause a fall in the quality of Members or reduce the variety of the composition of the House? The outcome is likely to be the reverse, and if the less wealthy Members are freed from the prepossession that they must earn more, then range of knowledge may be broadened, not narrowed."

यह है शास्त्री जी के प्रश्न का उत्तर । इससे पता लग जाता है कि सदस्यों का क्या काम है और उन्हें क्या काम करना है । हमारे घर में कोई लाइब्रेरी तक नहीं है । हम दस दीस अखबार भी नहीं मंगा सकते । अगर हम दस अखबार मंगा लें, तो 150 रुपये खर्च हो जाते हैं।

किसी भी मेम्बर को पूछ लीजिए कि उसको कितना काम करना पड़ता है । यह पार्टियों का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि हमारा इतना बड़ा देश है और इसकी आमदनी कितने परसेन्ट बढ़ गई है । 1954 में, जबकि यह बिल पास किया गया, हमें 400 रुपये मिलते थे । लगभग तीस सालों के बाद अब 500 रुपये किए

गए हैं । सदस्यों की तन्ख्वाह तो एक क्लर्क से भी गई-गुजरी है । एक क्लर्क को मेम्बर से ज्यादा मिलता है । चपरासी को भी ज्यादा मिलता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्लर्क को कितनी तन्ख्वाह मिलती है ।

This is the reply given in Parliament on 17th March, 1981 by Shri Maganbhai Barot:

> "The designation 'Assitant' is a general term and is generally applicable to Class III employees. The designation, duties and responsibilities and qualifications prescribed for direct recruitment may differ slightly from organisation to organisation. The total remuneration payable to Class III employees at the minimum and maximum in LIC, RBI, SBI and some other public sector undertakings is given in the statement attached."

According to the statement, a Class III employees gets as total emoluments per month Rs. 3406 in LIC Rs. 2580 in RBI, Rs. 1889 in SBI/ nationalised banks—Rs. 80 crores is the overtime this year—Rs. 1386 in Fertilizer Corporation of India, Rs. 1627 in Air India and Rs. 1308 in the Government.

16.29 hrs.

[SHRI K. RAJAMALLU *in the Chair*].

हमारी हालत तो क्लर्क से भी गई-गुजरी है । आप सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है । हम लोगों की हालत तो जो क्लर्क है उस से भी बदतर है ।

आप देखें जज को क्या मिलता है । एक जज को चार हजार रुपये मिलते हैं और बड़े जज को पांच हजार रुपये महीने मिलते हैं, और वह साल में केवल 194 दिन काम करते हैं । 120 दिन उनको छुट्टी रहती है, शिमला और दूसरे स्थानों में घूमने के लिए । बंगला उन का फ्री होता है । कितने उनको एलावेंसेज मिलते हैं । और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं । और हम लोग यहां पर अपना 20 साल का बुश शर्ट पहन कर आते हैं । तो बताइए हम कैसे अपना काम चला सकते हैं ?

हमारा जो प्रोटोकोल है उस में हमारी क्या हालत है ? कलेक्टर बाहर निकलता है कपड़े पहन कर, उसकी हालत देखिए । कलेक्टर एक जिले का आफिसर होता है, उसके नीचे पांच हजार आदमी काम करते हैं और हमारे नीचे हम और हमारी बूढ़ी औरत, यह हालत है हमारी ।

यह जो बिल मैंने रखा है मैं चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य जो यहां पर आए हुए हैं वह इस में पार्टिसिपेट करें । मैं उनको सुनूंगा और फिर एक एक बात का जवाब जो कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा वह उनकी सेवा में रखूंगा । लेकिन यह सब का सवाल है । हमारे माननीय मंत्री वेंकटसुब्बैया जी यह न समझें कि हमारी पार्टी से मूव कर दिया, हम हिपोक्रेट नहीं बनना चाहते । आज हम अपना खर्चा नहीं चला सकते । थोड़े दिनों में आप हमारे कपड़े भी छीन लेंगे, कुर्क करा लेंगे । इसलिए मैंने यह बिल रखा है ।

हमारी 68 करोड़ की जनता है, उसमें मासेज कभी कभी किधर भी जाती हों, कुछ भी बातें करती हों लेकिन लीडर में वह खासियत होनी चाहिए कि उनको समझा सके कि हमारी यह कठिनाई है । केवल आदर्शों की बात नहीं करनी चाहिए । हमारी एक पे एंड एलावेंसेज कमेटी है, वह क्यों नहीं इस बात को समझ कर आगे आती है ?

एक माननीय सदस्य : उस के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं ।

श्री मूल चंद डागा : वह बहुत गहरे व्यक्ति हैं, वह जब कहेंगे तो उनकी बात का बड़ा वजन होगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे और इस पर कम से कम एक महीने तक डिस्कशन होने दिया जाय ।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension

[Mr. Chairman]

of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : सभापति महोदय, जो अभी डागा साहब ने बिल रखा है, इस में कोई शक नहीं है कि इस बिल को मेरे ख्याल से बहुत पहले आ जाना चाहिए था । बहुत से लोग यहां पर ऐसे भी आए होंगे जो इस को अपोज भी करेंगे । लेकिन मैं यह जानता हूं, मेरे जाती नालेज में यह बात है कि उन में से बहुत से लोग वह हैं कि जब 1977 में हमने यह कोशिश की कि हमारी तन्ख्वाह और दूसरी सहूलियतें एम. पीज. को जो मिलती हैं वह उनके स्टेटस के मुताबिक चूंकि नहीं है, इसलिए हम ने एक कैम्पेन चलाया था जिस के अंदर 371 आदमियों से दस्तखत करा कर हमने एक मेमोरेंडम उस समय के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी भाई के सामने पेश किया था, उस वक्त का मेरा तजुर्बा है कि जो लोग आज यहां पर इस बिल को अपोज करेंगे, उनसे मेरी बात हुई, वह मुझसे यह बात कहते थे कि हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं चल सकता और हमें बड़ी परेशानी होती है लेकिन हमारी पार्टी की पालिसी ऐसी है कि हम इस को मुआफिकत नहीं कर सकते और हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे । लेकिन इस के बावजूद भी 371 लोगों ने दस्तखत किए । बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि पैसा तो नहीं लेकिन दूसरी सहूलियतें दफ्तर वगैरह की मिलनी चाहिए । नतीजा उस का भी यही है, वह भी यह महसूस करते हैं कि हमें जो तनख्वाह और सहूलियतें मिल रही हैं वह हमारे लिए मुनासिब और काफी नहीं हैं । (**व्यवधान**) मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं । मैं कहता हूं कि हमारी तमाम जरूरियात और स्टेटस के मुताबिक पार्लमेन्ट हमारी जिम्मेदारी ले लें और हमें एक पैसा भी न दें । आज जो 5 सौ पे और 1 हजार एलाउन्स का मिलता है उसको हम खत्म करने के लिए तैयार हैं लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का इन्तजाम किया जाए । मैं जानता हूं आज भी बहुत से मेम्बरान पार्लमेन्ट के बैंक एकाउन्ट्स में आपको ओवर-ड्राफ्ट मिलेगा और कभी-कभी तो हमारा चेक वापिस कर दिया जाता है । बड़ी संजीदगी के साथ लिख कर आ जाता है कि आप पार्लमेन्ट के आनरेबुल मेम्बर हैं लेकिन तीन हजार से ऊपर ओवर ड्राफ्ट हो चुका है जिसके आगे हम नहीं दे सकते हैं, यह चेक वापिस किया जाता है । अब इन हालात में भी अगर कोई साहब इस बिल को अपोज करते हैं तो उन्हें कोई आल्टरनेटिव बताना चाहिए कि किस तरह से हमारी जिन्दगी गुजारी जाए ?

हमें मकान दिया जाता है तो उसका किराया, फर्नीचर मिलता है तो उसका किराया, सिग्रेट के लिए अगर एश-ट्रे मिलती है तो उसका किराया, टेलीफोन है तो उसमें ट्रंक-काल के लिए कोई गुंजायश नहीं है । पानी का भी पैसा दीजिए, अभी मेरे पास साढ़े 12 सौ का बिल आया हुआ है, बिजली आयेगी तो उसका किराया, झाड़ू देने के लिए आदमी आयेगा तो उसका किराया । फिर गुजर कैसे हो ? या तो फिर आप यह तय कर लीजिए कि मेम्बर्स के पास कांस्टीटूएन्सी का कोई भी आदमी नहीं आयेगा और न ही कोई मेम्बर अपनी कांस्टीटूएन्सी में कभी जायेगा । मेम्बर अगर किसी को चाय पिलायेगा तो उसको पनिशमेन्ट दिया जायेगा--ऐसा ला आप बना दीजिए । अगर मेम्बर के यहां कोई आता है उसके लिए या तो आप गेस्ट हाउस का इंतजाम कीजिए या फिर ऐसा कानून बना दीजिए कि उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जायेगा, वह अपने रिप्रेजेन्टेटिव के यहां आया क्यों । इस सिलसिले में मुझे सन् 1977 का एक वाकया याद आ गया । मेरे एक साथी जिनके यहां उस वक्त इस तरह से एक मेहमान आए और आकर मुस्तकिल तरीके से रहने लगे । काफी दिन बीत गए तो उन्होंने एक दिन अपने मेहमान को समझाया, उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपका खर्चा बरदास्त नहीं कर सकता लिहाजा मुझे छुट्टी दें । फिर भी वे बाज नहीं आए । जब भी मेम्बर साहब खाने के लिए जायें तो वे उनके साथ चल दें । मजबूरन एक दिन उन्होंने पुलिस को टेलीफोन कर दिया कि एक आदमी इस तरह से गड़बड़ कर रहा है लिहाजा साढ़े दस बजे पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई । जब अगला एलेक्शन आया तो

उसमें वे मेम्बर साहब हार गए क्योंकि उनकी कांस्टीटूएन्सी में यह बात फैल गई कि उनके यहां जो मेहमान गया था उसको पुलिस पकड़ कर ले गई । यह किसी ने नहीं देखा कि एक महीने से वह मेहमान परेशान कर रहा था । उल्टे उनको सजा यह मिली कि एलेक्शन में हार गए ।

ऐसी हालत में जो भी इस बिल का अपोजीशन करें वे बतायें कि हम क्या करें ? आज कोई भी कांस्टीटूएन्सी 300 किलोमीटर लम्बी या कम से कम 150 किलोमीटर लम्बी चौड़ी होती है । अब अगर पक्की सड़क भी हो और 150 किलोमीटर भी कोई एम. पी. अपना झंडा लगाकर गाड़ी पर चला जाए और लौट कर आए तो एक दिन में ही 400 रुपये का बिल बन जाता है । अब साल में 15-20 दिन भी अगर वह अपनी कांस्टीटूएन्सी में चला जाए तो कुल 19,500 रुपये साल में जो उसको मिलते हैं वह सिर्फ इसी मद में चले जायेंगे । किसी ने कहा डागा जी को 30,000 रु. मिलते हैं तो डागा जी रूलिंग पार्टी के मेम्बर हैं, बोलने वाले हैं, इंफ्लूएंशल हैं, हो सकता है वे चार-पांच कमेटीज में रख दिए गए हों लेकिन हमारी तरफ के मेम्बर को, जिसे 1500 रु. ही मिलते हैं उसको साल में 18,000 रु. ही हुए । इस प्रकार 19,500 रुपये हमको पूरे साल में मिलते हैं और डागा जी को जो 11,500 रु. ज्यादा मिलता है, वे उसको तकसीम करें, वे हम से ज्यादा कैसे ले रहे हैं । इसके बाद आप देखिए एजूकेशन का सवाल है और यदि हम कहीं पर जाना चाहते हैं, बाहर से डेलीगेशन्स आते हैं, उनमें हमको बुलाया जाता है, लेकिन हम तो यह सोचते हैं कि यदि गए तो 20-25-30 रु. टैक्सी में लग जाएगा और यदि इतने रुपये टैक्सी में दे दिए तो सुबह का नाश्ता कहां से आएगा जो आपके यहां 20 आदमी मेहमान बन कर रह रहे हैं । यदि नाश्ते में केवल डबल रोटी भी देंगे तो काफी पैसा लग जाएगा । इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है । मुझे यकीन है जब जवाब देंगे तो नाक उलटी ही पकड़ेंगे सीधी नहीं पकड़ेंगे, हमें कन्वेंस दी जाए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैसा भी न दिया जाए, लेकिन हमारी जरूरतों की गारन्टी ले ली जाए । वह दे नहीं सकते हैं क्योंकि यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है ।

डागा जी ने एक और ज्यादती की है कि एलाउन्स 65 रु. होना चाहिए, मैं कहता हूं कि 101 रु. क्यों न हो उत्तर प्रदेश के अन्दर एक विधायक को 40 रु. रोज एलाउन्स का मिल रहा है और इसके साथ-साथ टेलीफोन फ्री, डेढ़ हजार रु. सैलरी है, मकान फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, किसी को भी अपने साथ 15 हजार किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास में ले जा सकता है, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी । इसके अलावा सफाई करने वाला आदमी फ्री, आठ कमरों में एक नौकर फ्री ये सारी चीजें दी जाती हैं । इससे ज्यादा बढ़ कर बदकिस्मती और क्या हमारी हो सकती है, यह आपके साथ भी है, चाहे रूलिंग पार्टी वाले थोड़ा कम मुतासिर होते हैं और अपोजीशन वाले ज्यादा हो जाते हैं । यहां पर यदि कोई मामला उठाया जाता है तो स्पीकर साहब कह देंगे कि यह स्टेट सब्जैक्ट है--रिजेक्टेड । इस प्रकार हम यहां भी मारे गए और तनख्वाहों में भी मारे गए । आप जानते हैं कि कि दीनदयाल उपाध्याय जी का देहान्त हो गया क्योंकि उनका एटेन्डेंट थर्ड क्लास में था और वे फर्स्ट क्लास में थे । वहां कोई डाक्टर नहीं, हकीम नहीं, क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है । एम. पीज. तो एक तमाशा बन कर रह गए हैं । शेरवानीजी की भी ऐसी ही हालत थी ।

इत्तफाक की बात यह है कि यदि हमें किसी जलसे में जाना पड़ जाए और उसकी बीबी भी पोलीटिक्स में हो और एम. पी. न हो और इस वजह से हम को भी सैकेंड क्लास में जाना पड़ेगा । सैकेंड क्लास में न तो वहां पर बोलने के लिए तैयारी हो सकती है, लिखाई-पढ़ाई नहीं हो सकती है और जब वहां पर उतरेंगे तो रिक्शे लिए भी पैसे नहीं होंगे । इस प्रकार ये सारी बातें हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सी. पी. आई वाले विरोध कर रहे हैं और इनके भाषण का सारा डाटा सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री रशीद मसूद : यह तो कर ही रहे हैं। सी. पी. आई. ने बताया कि हम नाक सीधी पकड़ रहे हैं और ये उल्टी पकड़ रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। डागा जी ने इसमें 65 रु. की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि 100 रु. होनी चाहिए। दूसरे-बीवी के लिए फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए आप एक सीमा मुकर्रिर कर दें कि पांच या दस किलोमीटर की। तीसरे एटेंडेंट को भी फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए। क्योंकि यह तो आपके सामने है कि किस प्रकार रेल में दो-तीन हादसे हो चुके हैं। एटेंडेंट वहां पर न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनको रेलवे में जगह नहीं मिलती है। यह होता है कि हमने यहां पर रिजर्वेशन कराया और जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता लगा कि रिजर्वेशन नहीं था। मंत्री जी से शिकायत करते हैं तो कहा जाता है कि होगा। इत्तफाक से उसी नाम का दूसरा आदमी ट्रैवल कर रहा है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने एक बार स्टीफन साहब से अपने टेलीफोन के बारे में शिकायत की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को लिख कर भेजा, लेकिन फिर भी तीन दिनों तक टेलीफोन ठीक नहीं हुआ। 5वें दिन स्टीफन साहब ने मुझे एक खत लिखा जो 8-10 दिन के बाद पहुंचता है कि आप का टेलीफोन ठीक कर दिया गया था। हम ने मधु साहब को टेलीफोन किया था, उन्होंने कहा था कि टेलीफोन ठीक है। मधु साहब हमारे आफिस में काम करते हैं, उन्होंने आफिस से टेलीफोन की शिकायत दर्ज कराई थी, इस लिए उन्होंने हो सकता है मधु साहब को दफतर में टेलीफोन कर के पूछा हो, लेकिन टेलीफोन तो मेरे घर का खराब था। वह कहते हैं कि घर पर टेलीफोन किया था, वहां मधु साहब से बात हुई थी। यह हालत आपकी ब्यूरोक्रेसी की है। मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं कि जिस किस्म की दिक्कत में मैं मुब्तला हूं, हो सकता है कल जब आप इधर आयें तो आप को भी ऐसी दिक्कत हो सकती है।

चेयरमैन साहब, इन अलफाज के साथ मैं डागा साहब के बिल को सपोर्ट करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि वह इस बिल को यहां लाये।

[شری رشید مسعود (سہارنپور) :

سبھاپتی مہودے - جو ابھی ڈاگا صاحب نے بل رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے - کہ اس بل کو میرے خیال سے بہت پہلے آ جانا چاہئے تھا - بہت سے لوگ یہاں پر ایسے بھی آئے ہوں گے جو اسکو اپوز بھی کریں گے - لیکن میں یہ جانتا ہوں میرے ذاتی نالج میں یہ بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جب ۱۹۷۷ ع میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہماری تنخواہیں اور دوسری سہولتیں ایم پیز کو جو ملتی ہیں وہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق چونکہ نہیں ہے اسلئے ہم نے ایک کمپین چلایا تھا جسکے اندر ۳۷۱ آدمیوں سے دستخط کرا کر ہم نے ایک میمورنڈم اس سمے کے پردھان منتری شری مرارجی بھائی کے سامنے پیش کیا تھا اس وقت کا میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ آج یہاں پر اس بل کو اپوز کریں گے ان سے میری بات ہوئی وہ مجھ سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل سکتا اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن ہماری پارٹی کی پالیسی ایسی ہے کہ ہم اسکی مخالفت

نہیں کر سکتے اور ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی ۳۷۱ لوگوں نے دستخط کئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ پیسہ تو نہیں لیکن دوسری سہولتیں دفتر وغیرہ کی ملنی چاہئے نتیجہ اسکا یہی ہے وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں جو تنخواہیں اور سہولتیں مل رہی ہیں وہ ہمارے لئے مناسب اور کافی نہیں ہے - میں انکی بات سے متفق ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری تمام ضروریات اور اسٹیٹس کے مطابق پارلیامنٹ ہماری ذمہ داری لے لے اور ہمیں ایک پیسہ بھی نہ دے - آج جو پانچ سو روپئے اور ایک ہزار الاونس کا ملتا ہے اسکو ہم ختم کرنے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انکو پورا کرنے کا انتظام کیا جائے - میں جانتا ہوں آج بھی بہت سے ممبران پارلیمنٹ کے بینک اکاونٹس میں آپکو اوور ڈرافٹ ملے گا اور کبھی کبھی تو ہمارا چیک واپس تک بھی آجاتا ہے - بڑی سنجیدگی کے ساتھ لکھکر آ جاتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے آنریبل ممبر ہیں لیکن ۳۰۰۰ سے اوپر اور ڈرافٹ ہو چکا ہے جس کے آگے ہم نہیں دے سکتے ہیں یہ چیک واپس کیا جاتا ہے -

اب ان حالات میں بھی اگر کوئی صاحب اس بل کو اپوز کرتے ہیں تو انہیں کوئی آلٹرنیٹو بتانا چاہئے کہ کس طرح سے ہماری زندگی گذاری جائے -

ہمیں مکان دیا جاتا ہے تو اسکا کرایہ فرنیچر ملتا ہے تو اسکا کرایہ سکریٹ کے لئے اگر ایکسٹرے ملتی ہے تو اسکا کرایہ اگر ٹیلیفون ہے تو اس میں ٹرنک کالس کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے پانی کا بھی پیسہ دیجئے - ابھی میرے پاس ساڑھے بارہ سو کا بل آیا ہوا ہے بجلی آئیگی تو اسکا کرایہ - جھاڑو دینے کے لئے آدمی آئے گا اسکا کرایہ پھر گذر کیسے ہو - یا تو پھر آپ یہ طے کر لیجئے کہ ممبرس کے پاس کنسٹیچوینسی کا کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی ممبر اپنی کانسٹی چوینسی میں کبھی جائے گا ممبر اگر کسی کو چائے پلائے گا تو اس کو پنشمینٹ دیا جائے گا - ایسا لا آپ بنا دیجئے اگر ممبر کے یہاں کوئی آتا ہے اس کے لئے یا تو آپ گیسٹ ہاوس کا انتظام کیجئے یا پھر ایسا قانون بنا دیجئے کہ اسکو تہاڑ جیل بھیج دیا جائے گا - وہ ابھی ریپریزینٹیٹو کے ہاں آیا کیوں - اس سلسلے میں مجھے ۱۹۷۷ء کا ایک واقعہ یاد آگیا

[شری رشید مسعود]

بھی ہو اور ۱۵۰ کلو میٹر بھی کوئی ایم پی جھنڈا لگا کر گاڑی پر چلا جائے اور لوٹ کر آئے تو ایک دن میں ہی چار سو روپئے کا بل بن جاتا ہے - اب سال میں پندرہ بیس دن بھی اگر وہ اپنی کانسٹی چوینسی میں چلا جائے تو کل ۱۹۵۰۰ روپئے سال میں جو اسکو ملتے ہیں وہ صرف اسی مد میں چلے جائیں گے کسی نے کہا ڈاکا جی کو ۳۰۰۰۰ روپئے ملتے ہیں تو ڈاکا جی نے رولنگ پارٹی کے ممبر ہیں بولنے والے ہیں انفلوئینشل ہیں ہو سکتا ہے وہ چار پانچ کمیٹیز میں رکھ دئے گئے ہوں لیکن ہماری طرف سے ممبر کو جسے پندرہ سو بھی ملتے ہیں انکو سال میں اٹھارہ ہزار ہی ہوئے -

اس پرکار ۱۹۵۰۰ روپئے ہمکو پورے سال میں ملتا ہے اور ڈاکا جی کو جو ۱۱۵۰۰ روپئے زیادہ ملتا ہے وہ اسکو تسلیم کریں وہ ہم سے زیادہ کیسے لے رہے ہیں - اسکے بعد آپ دیکھئے ایجوکیشن کا سوال ہے اور یدی ہم وہیں پر جانا چاہتے ہیں باہر سے ڈیلیگیشنس آتے ہیں ان میں ہم کو بلایا جاتا ہے - لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یدی گئے تو ۲۰ - ۲۵ - ۳۰ روپئے ٹیکسی میں

میرے ایک ساتھی تھے جن کے یہاں اس وقت اس طرح سے ایک مہمان آئے اور آکر مسلسل طریقہ سے رہنے لگے کافی دن بیت گئے تو انہوں نے ایک دن اپنے مہمان کو سمجھایا ان سے درخواست کی کہ میں آپکا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا مجھے چھٹی دیں پھر بھی وہ باز نہیں آئے جب بھی ممبر صاحب کہانے کھلئے جائیں؛ وہ انکے ساتھ چل دیں مجبوراً ایک دن انہوں نے پولیس کو تیلیفون کر دیا کہ ایک آدمی اس طرح سے گڑ بڑ کر رہا ہے لہذا سارے دس بجے پولیس آئی اور انکو پکڑ کر لے گئی - جب اگلا الیکشن آیا تو اس میں وہ ممبر صاحب ہار گئے کیونکہ انکی کانسٹی چیونسی میں یہ بات پھیل گئی کہ انکے ہاں جو مہمان گیا تھا اسکو پولیس پکڑ کر لے گئی یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک مہینے سے وہ مہمان پریشان کر رہا تھا الٹے انکو سزا یہ ملی کہ الیکشن میں ہار گئے-

ایسی حالت میں جو بھی اس بل کا اپوزیشن کرے وہ بتائیں کہ ہم کیا کریں - آج بھی کوئی کانسٹی چوینسی ۳۰۰ کلومیٹر لمبی یا کم سے کم ۱۵۰ کلومیٹر لمبی چوڑی ہوتی ہے اب اگر پکی سڑک

لگ جائے گا اور یدی اتنے روپئے ٹیکسی میں دے دئے تو صبح کا ناشتہ کہاں سے آئیگا جو آپکے یہاں تین آدمی مہمان بن کر رہ رہے ہیں - یدی ناشتے میں کیول ڈبل روٹی بھی دیں گے تو کافی پیسہ لگ جائے گا - اس اور دھیان نہیں جا رہا ہے - مجھے یقین ہے جب جواب دیں گے تو ناک الٹی ہی پڑے گی سیدھی نہیں پڑے گی - ہمیں کلوینس دی جائے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پیسہ بھی نہ دیا جائے لیکن ہماری ضرورتوں کی گارنٹی لے لی جائے - وہ دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے -

ڈاکٹر جی نے ایک اور زیادتی کی ہے کہ الاؤنس ۶۵ روپئے ہونا چاہئے میں کہتا ہوں کہ ۱۰۱ روپئے کیوں نہ ہو - اتر پردیش کے اندر ایک ودھایک کو ۴۰ روپئے روز الاؤنس کا مل رہا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ ٹیلیفون فری ڈیڑھ ہزار روپئے سیلری ہے مکان فری پانی فری بجلی فری کسی کو بھی اپنے ساتھ ۱۵ ہزار کلو میٹر تک فرسٹ کلاس میں لے جا سکتا ہے پورے ہندوستان میں کہیں بھی - اسکے علاوہ صفائی کرنے والا آدمی فری آٹھ کمروں میں ایک نوکر فری یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے یہ آپکے ساتھ بھی ہے چاہے رولنگ پارٹی والے تھوڑا کم متاثر ہوتے ہیں اور اپوزیشن والے زیادہ ہو جاتے ہیں- یہاں پر یدی کوئی معاملہ اٹھایا جاتا ہے تو اسپیکر صاحب کہہ دیں گے کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے - ریجیکٹڈ - اس پرکار ہم یہاں بھی مارے گئے اور تنخواہوں میں بھی مارے گئے - آپ جانتے ہیں کہ دین دیال اپادھیائے جی کا دیہانت ہو گیا کیونکہ انکا اٹینڈینٹ تھرڈ کلاس میں تھا اور وہ فرسٹ کلاس میں تھے - وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں حکیم نہیں کیا ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایم - پیز تو ایک تماشا بن کر رہ گئے ہیں - شیروانی جی کی بھی ایسی ہی حالت تھی -

اتفاق کی بات یہ ہے کہ یدی ہمیں کسی جلسے میں جانا پڑ جائے اور اسکی بیوی بھی پولیٹکس میں ہو اور ایم - پی نہ ہو اور اس وجہ سے ہم کو بھی سیکنڈ کلاس میں جانا پڑے گا - سیکنڈ کلاس میں نہ تو وہاں پر ٹوالیٹ کے لئے تیاری ہو سکتی ہے لکھائی پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے اور جب وہاں پر اتریں گے تو رکشے کے لئے

[شری رشید مسعود]

بھی پیسے نہیں ہونگے - اس پرکار یہ ساری باتیں ہیں -

شری ہری کیش بہادر (گورکھپور): سی - پی - آئی والے ورودھ کر رہے ہیں اور ان کے بھاشن کا سارا ڈاٹا سپلائی کر رہے ہیں -

شری رشید مسعود: یہ تو کر ہی رہے ہیں - سی - پی - آئی نے بتایا کہ ہم ناک سیدھی پکڑ رہے ہیں اور یہ الٹی پکڑ رہے ہیں - میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں - ڈاٹا جی نے اس میں ۷۵ روپئے کی بات کہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ۱۰۰ روپئے ہونی چاہئے - دوسرے - بیوی کے لئے فرسٹ کلاس کا پاس ملنا چاہئے چاہے اس کے لئے آپ ایک سیما مقرر کر دیں کہ پانچ یا دس کلو میٹر کی - تیسرے اٹینڈینٹ کو بھی فرسٹ کلاس کا پاس ملنا چاہئے - کیونکہ یہ تو آپکے سامنے ہیں کہ کس پرکار ریل میں دو تین حادثے ہو چکے ہیں - یہ اٹینڈینٹ وہاں پر نہ ہونے کی وجہ سے انکی مرتیو ہو گئی - کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انکو ریلے میں جگہ نہیں ملتی ہے - یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر ریزرویشن کرایا اور جب اسٹیشن پر پہنچے تو پتہ لگا کہ ریزرویشن نہیں تھا - منتری جی سے شکایت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہو گا - اتفاق سے اس نام کا دوسرا آدمی ٹریول کر رہا ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا - میں نے ایک بار اسٹیشن صاحب سے اپنے ٹیلیفون کے بارے میں شکایت کی اسکے بعد پرائم منسٹر کو لکھ کر بھیجا لیکن پھر بھی تین دنوں تک ٹیلیفون ٹھیک نہیں ہوا - پانچویں دن اسٹیٹ صاحب نے مجھے ایک خط لکھا جو آٹھ دس دن کے بعد پہنچتا ہے کہ آپکا ٹیلیفون ٹھیک کر دیا گیا تھا - ہم نے مدھو صاحب کو ٹیلیفون کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ٹیلیفون ٹھیک ہے مدھو صاحب ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں انہوں نے آفس سے ٹیلیفون کی شکایت درج کرائی تھی اس لئے انہوں نے ہو سکتا ہے مدھو صاحب کو دفتر میں ٹیلیفون کر کے پوچھا ہو لیکن ٹیلیفون تو میرے گھر کا خراب تھا وہ کہتے ہیں کہ گھر پر ٹیلیفون کیا تھا وہاں مدھو صاحب سے بات ہوئی تھی یہ حالت آپ کی بیورو کریسی کی ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی دقت میں میں مبتلا ہوں ہو سکتا ہے کل جب آپ افسر

آئیں تو آپ کو بھی ایسی دقت
ہو سکتی ہے -

چیئرمین صاحب میں ان الفاظ
کے ساتھ میں ڈاگا صاحب کے بل
کو سپورٹ کرتا اور انکو مبارکباد
دیتا ہوں کہ وہ اس بل کو
یہاں لائے -]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मेरा तो ऐसा विचार है कि यह एक ऐसा बिल है जिस को बिना किसी वाद-विवाद के पारित कर देना चाहिए, सभी सदस्यों को एक मत से इसे पारित करना चाहिये ।

सभापति महोदय, डागा साहब ने जो बिल प्रस्थापित किया है उस में 4 मुख्य संशोधन हैं । पहला यह कि जो 500 रुपया माहवार हम को तनख्वाह मिलती है उसको 800 रुपया कर दिया जाय . .

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : 1000 रुपये कर दिया जाय ।

श्रीमती कृष्णा साही : जो 51 रुपये रोज दैनिक भत्ता मिलता है उसको 65 रुपया कर दिया जाय . . . .

श्री वृद्धि चन्द जैन : 101 रुपया कर दिया जाय । इन्होंने अपने ओरिजनल बिल में संशोधन कर दिया है ।

श्रीमती कृष्णा साही : हां, इन्होंने संशोधन कर दिया है कि 101 रुपया कर देना चाहिये ।

तीसरे, सहयात्री जिस को स्पाउस कहते हैं—उसके लिए द्वितीय श्रेणी का पास दिया जाता है . . .

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : उसको स्पाउस नहीं कहते हैं । स्पाउस के मायने हस्बैण्ड तथा वाइफ ।

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा मतलब सहयात्री से है, कम्पेनियन से है, स्पाउस की जगह शब्द सहयात्री ही होना चाहिये । उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिये ।

उस के बाद चिकित्सा के सम्बन्ध में इन्होंने कहा कि उस में परिवार के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिये । टेलीफोन की सुविधा के बारे में इन्होंने कहा है। जो 500 रुपये का भत्ता मिलता है जिस में डाक, तार, पानी, बिजली इत्यादि है उस को बढ़ाकर 750 रु. करना चाहिये। इस तरह से इन्होंने जितनी बातें संशोधन के रूप में रखी हैं, वे सब व्यावहारिक हैं और आज के जमाने में जब कि मंहगाई बढ़ती जा रही है, ये सुविधायें अवश्य दी जानी चाहिये । इन के लिये हमें पैसा मिले या न मिले, लेकिन जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है अगर सरकार इन सब बातों की जवाबदेही अपने ऊपर ले ले तो तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन जवाबदेही भी तो तभी आयेगी जब कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा । आज संसार में जितने देश हैं, सभी देशों की तुलना में हमारे यहां सब से कम पैसा सांसदों को मिलता है । हाउस आफ कामन्स में, अमरीकी सीनेटर्स को, जो वेतन और सुविधायें दी जाती हैं, उन की तुलना में हमारे यहां बहुत कम दिया जाता है । इतना ही नहीं, अब तो राज्य विधान मंडलों में, जहां पहले 10 रुपये रोज मिलते थे, अब 45 और 50 रुपये रोज मिलने लगे हैं । छोटे छोटे प्रान्त में जिस की आबादी बहुत कम है वहां भी 45 और 51 रुपये रोज मिलते हैं ।

श्री रामसिंह यादव : राजस्थान में 51 रुपये रोज है ।

श्रीमती कृष्णा साही : उस अनुपात से यदि लोक सभा में देखा जाय, तो सन 1952 में जो 51 रुपये रोज तय हुए थे, वही अब तक चले आ रहे हैं । मंहगाई चार गुना बढ़ गई है, लेकिन हम लोग तो केवल दो-गुना की बात कर रहे हैं । इस लिये मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, इस में हिपोक्रेसी की कोई बात नहीं होनी चाहिये ।

[श्रीमती कृष्णा साही]

सभापति महोदय, पंजाब में 45 रुपये रोज भत्ता मिलता है । इस के अलावा गाड़ी खरीदने के लिये . . .

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पाखण्ड पूरा आप लोग रचाये हुए हैं, कोई सिद्धान्त की बात करे तो वह पाखण्डी हो गया, यह कहां से सीख लिया है । आप अपनी बात रखिये ।

श्रीमती कृष्णा साही : 45 हजार रुपया पंजाब में मकान बनाने के लिए लोन दिया जाता है और गाड़ी खरीदने के लिये भी 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है । हरियाणा में भी यही बात है और वहां पर भी गाड़ी खरीदने के लिए 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है । राजस्थान में, सिक्किम में और तामिलनाडु आदि कई जगहों पर मकान रहने के लिए फ्री दिया जाता है लेकिन हमारे यहां मकान का भी किराया लगता है । मकानों की हालत खराब है और जनता में यह भ्रम फैला हुआ है कि मेम्बरों को रहने के लिए मकान फ्री दिया जाता है, टेलीफोन फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है और पानी फ्री मिलता है । मेरा कहना यह है कि जनता के बीच में यह भ्रम फैला हुआ है कि हम लोग शान व शौकत से रहते हैं और हमारा इन चीजों पर कोई खर्च नहीं होता है । मेरा एक प्रस्ताव भी इस के बारे में था और इन की भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्त्तमान सेक्रेटेरिएट सुविधा या पैसों से क्या होगा । आप एक एसिसटेंट 500 रुपये में नहीं रख सकते हैं, एक स्टेनोग्राफर नहीं रख सकते हैं । स्थिति यह है कि सुबह से ले कर 11 बजे तक जब तक हम पार्लियामेंट हाउस आते हैं, हर 5 मिनट के बाद घंटी बजती है और अगर हम बाथरूम में भी होते है या पूजा करते रहते हैं तो हमें बाहर दौड़ कर देखना होता है कि कौन कौन है या फिर जो हमारे घर में रहते हैं, वे देखते हैं लेकिन वे कितने है । छोटा नौकर अगर है, तो वह कितना क्या कर सकता है ।

दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि हमारा पोस्टल स्टेम्पस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है । 8 लाख से 10 लाख का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, 6 विधान सभाओं या 5 विधान सभाओं को मिला कर हम प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन उस के लिए हमें बहुत कम पैसा मिलता है । इसके अलावा मेरा यह कहना है कि विधान सभा में एक मेम्बर को 15 हजार टेलीफोन काल फ्री हैं और हम को भी 15 हजार टेलीफोन काल फ्री हैं । अगर 6 विधान सभाओं का हिसाब हम लगाएं, तो उसके अनुपात में हम को बहुत कम टेलीफोन काल फ्री है । हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं क्योंकि हमें खानाबदोशों की तरह से जिन्दगी बितानी होती है । इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अगर पति और पत्नी साथ चलते हैं और अगर किसी का पति या पत्नी नहीं है और उसके साथ कोई सहयात्री जाता है, तो उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए । अब होता क्या है कि खुद तो फर्स्ट क्लास में बैठा है । और दूसरा सैकेन्ड क्लास में बैठा है । अब पत्नी कोई गठरी तो है नहीं कि सेशन के टाइम पर लाकर रख दी और सेशन के बाद फिर ले कर चले गये । वह कोई मोटर तो है नहीं कि जहां चाहा रख दिया । इसलिए मेरा कहना यह है कि पति या पत्नी या सहयात्री अगर साथ जाते है, तो उनको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए । हमारे एक बहुत बुजुर्ग बिहार के सदस्य थे बेचार । उनकी मृत्यु हो गई और 10-15 स्टेशन के बाद जा कर किसी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई । मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस के लिए आप घबड़ाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी कि हमने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली । सबसे बड़ी बात यह है कि एक संसद सदस्य की जो जिम्मेदारी होती है, कम से कम उस जिम्मेदारी को वहन करने लायक हम को मिलना चाहिए । 30-40 लोग हमारे यहां रोज आते हैं और उन को चाय पिलानी होती है । शास्त्री जी तो चीनी खाते नहीं इसलिए उनको चीनी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह कैसे कहती हैं, मैं 6-7 आदमियों को रोज चाय पिलाता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं यह कहती हूं कि एक तरफ तो ये हमारे मंत्री जी को

कहते हैं कि हम को आप फैसेलिटीज नहीं देते और दूसरी तरफ सिद्धान्त की बात करते हैं । इन की कथनी और करनी में फर्क है और यह फर्क नहीं होना चाहिए । जो कथनी और करनी में फर्क करते हैं, वही सिद्धान्त की बात करते हैं । हम लोग सिद्धान्त की बात सही जगह पर करते हैं । इसमें इतनी वित्तीय इन्वोल्वमेंट की बात नहीं है । इसलिए मेरा यह अनुरोध होगा कि जहां फ्री हाउसेस की बात होती है, उसके बारे में सोचा जाए । आन्ध्र प्रदेश में फ्री मकान दिया जाता है और जैसा मैंने सुना है मद्रास में यूटेंसिल्स और लीनेन सब फ्री मिलता है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि विधान सभा के सदस्य हमको चिट्ठी लिख देते हैं कि इतने आदमी आ रहे हैं, इनकी देखरेख करना । अगर उनकी देखरेख नहीं होती है, तो फिर वोट के समय वे याद रखते हैं, एम. एल. ए. से लेकर जनता तक कि हम वहां गये और हमें एक पियाली चाय भी नहीं पिलाई गई । मैं परसों की बात करती हूं रात को साढ़े 11 बजे हमारे क्षेत्र से 25-30 आदमी हमारे यहां आ गये । एक तो हम महिला हैं । हमारे भाई लोगों को शायद कुछ कम परेशानी होती होगी । एक महिला होने के नाते हमें अधिक परेशानी होती है । जिस ट्रेन से वे आये थे, वह ट्रेन लेट थी । बिचारे मर्द, औरत, बच्चे थे, सभी हमारे यहां आये और उन लोगों को हमें ठहराना ही होता है क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व तो करती हूं ।

हम लोगों को जो मकान मिले हैं उसका पर्याप्त किराया लिया जाता है । फर्नीचर के लिए पांच हजार की सीलिंग लगा रखी है कि इस से ज्यादा फर्नीचर हमको नहीं मिल सकता है उससे ज्यादा का किराया काफी देना पड़ता है । डोर मेट जो हम लेते हैं उनका हमें दो रुपये महीने किराया देना पड़ता है । हमें दो तरह का फर्नीचर मिलता है एक मूवेबल और दूसरा नान मूवेबल हमारे यहां राइटिंग ब्यौरा होता है, उसका भी हम से किराया चार्ज किया जाता है । वह दीवार के साथ लगा हुआ है लेकिन उसको भी मूवेबल माना जाता है । इस के अलावा हमारे यहां जमादार, मेहतर आता है, उसको अलग देना पड़ता है । इस तरह से बहुत से हमारे एडीशनल खर्च हो जाते हैं ।

ड्राइंग रूम में जो राइटिंग ब्यूरो फिकस है पता नहीं उसको आप कैसे मूवेबल मानते हैं । वह दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकता है लेकिन उसको भी मूवेबल मान कर उसका किराया चार्ज किया जाता है । ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें देखना है ।

ये सारी बातें कहने का मेरा मतलब यही है कि आप स्टेण्डर्ड आफ लीविंग की बात को और सुविधाओं की बात को छोड़ दीजिए लेकिन हमारे जो उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए तो हमें आवश्यक साधन प्रदान कीजिए, बेशक हमें आप सुखसुविधाएं न दें । हमें इतना तो दीजिये कि हमारे यहां तनावपूर्ण वातावरण न रहे । हमारी जिन्दगी एक खानाबदोश की सी जिन्दगी होती है। घर में न पति पत्नी को देखे, बच्चे मां को या पिता को न देखे और इस प्रकार से हमारी जिन्दगी तनावपूर्ण बनी रहे । इस से निकालने के लिए भी और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए, उनका अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें उचित सुविधाएं तो प्राप्त होनी ही चाहिए । चाहे मंत्री हों, चाहे सदस्यगण हों, उनकी सुविधाएं आजकल बहुत कम हैं । इन से हमारा दिन-रात का काम नहीं चल सकता है । हमें दिन-रात काम करना पड़ता है । इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बिल को पास करना जरूरी है । मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इस को सर्वसम्मति से पारित करें ।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Mr. Chairman, Sir, the hon. Members have pointed out that if we say that salary and allowances should not be increased, it would be a hypocrisy. I think, those hon. Members who call us hypocrites, most probably live in a high society. They have never gone to the villages; they have never seen the plight of villagers.

It is a fact that the prices have been increasing. But the Government has been pleading with us that they have succeeded in arresting the price

[Shri Sudhir Giri]

rise. It is a member of the ruling party who has pointed out that the prices have been increasing day by day.

17.00 hrs.

It is a fact that prices have been increasing but we should keep in mind the fact that we are the representatives of the people, who live in the villages and in the basti areas of the towns and cities. We know very well how much suffering they have to undergo during these price-spiralling days and the Planning Commission has pointed out in its report that more than 50 per cent of the people, most probably 50.6 per cent of the total population, live below the poverty line. But our assesmsent in this respect is that more than 70 per cent of the people in India live below the poverty line. Most probably, many Members who adorn this august House are not fully aware of the lives of the villagers who live even a beastly life. I say so because in a hut boys and girls and husband and wife and cows and buffaloes and goats and sheep live together side by side. There is no difference between the beasts and the human beings.

A demand has been made for payment of Rs. 65/- during the session period. But, you must remember that even an average family in the villages cannot earn Rs. 50/- per month. Most probably, many of our Members do not know this fact.

The increase in salaries and allowances has been justified on the ground that efficiency should be maintained. But, to maintain the efficiency of the hon. Members I would suggest to the Government that Stenographers or typists should be provided to them when they need and if we do this, our efficiency can be maintained and we can act as Members of Parliament efficiently. With these words I oppose the Bill.

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मोहतरम डागा साहब ने सेलरी एण्ड अलाउंसेस बढ़ाने के बारे में जो बिल प्रस्तुत किया है, उस बिल का मैं समर्थन करते हुए चंद बातें कहना चाहता हूं ।

जैसा कि डागा साहब ने इस एवान के सामने डिटेल में इस मसले को पूरी तरह उभारा, कोई टापिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, जिस पर मैं और कुछ कह सकूं । लिहाजा उन बातों पर मैं न जाते हुए चन्द प्वाइंट आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो कि शायद बहुत सारे सदस्यों के जहन में नहीं होंगे । खासतौर पर उन इलाकों के बारे में जो ट्राइबल हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो रेगिस्तानी इलाके हैं—जैसे राजस्थान है, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहां पर क्या-क्या मुश्किलात मेंबरों को भुगतनी पड़ती है, उन मुश्किलात को देखते हुए डागा साहब ने अपने बिल में मेम्बरों की तनखाह जो 500 रुपये के बजाए एक हजार रुपया बढ़ाने के लिए और अलाउंसेस 51 रुपये के बजाए 101 रुपये करने के लिए कहा है, मैं समझता हूं कि किसी हद तक वह भी कम होगा । उन हालात का सही ढंग से जायजा लिया जाए, जिन हालत में ट्राइबल्स एरिया में और पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के पास मेंबर्स को जाना पड़ता है । जहां तक रेलवे पास का सम्बन्ध है स्पाउज के लिए भी फ्री फर्स्ट क्लास पास की बात इस बिल में कही गई है । यह ठीक बात है । वह मिलना चाहिये । लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन की कान्स्टीच्यून्सी में रेलवे लाइनें ही नहीं हैं । बहुत से ऐसे आनरेबल मेम्बर्ज हैं जिन के इलाकों में रेलवे का जाल बिछा हुआ है लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां रेलवेज ही नहीं हैं। वहां पर यह फ्री रेलवे पास की बात बेमानी बन जाती है । फ्री रेलवे पास पर आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आप भूखे तो घूम नहीं सकते हैं । जेब में भी कुछ होना चाहिए । मैं समझता

हूं कि जहां रेल की जिस कान्स्टीट्यूंसी में फैसिलिटीज नहीं है वहां पर अगर कोई मैम्बर दौरे पर जाता है, तो उसके लिए कोई एक्सटरा एलाउंस होना चाहिए ताकि उसको कुछ कम्पेंसेट किया जा सके। जहां तक मैम्बरों को फ्री फर्स्ट क्लास रेलवे पास का सवाल है उनको आप एयर कंडिशन में सफर करने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं ? जब कि ब्यूरोक्रेट्स जैसे डिप्टी सैक्रेटरी, ज्वायंट सैक्रेटरी, सैक्रेटरी एयर कंडिशन में जा सकते हैं और कहा जाता है कि उनका स्टेटस हम से नीचे है। अगर नीचे है तो वे तो एयर कंडिशन में सफर करेंगे और हम फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे ? क्या यह एक मैम्बर की डिग्निटी नहीं होगी ? लिहाजा आपको एयर-कंडिशन में मैम्बर्ज को सफर करना एलाऊ करना चाहिए। स्पाउज के लिए रेलवे कन्सैशन के लिए जो एमेंडमेंट उन्होंने दिया है उसको मैं स्पोर्ट करता हूं। लेकिन साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जब सैशन होता है तो स्पाउज को भी फ्री फर्स्ट क्लास रेल में सफर की इजाजत होती है तो लद्दाख जैसे इलाकों में तो नवम्बर के महीने से लेकर 6-7 महीने के लिए रास्ते बन्द हो जाते हैं और मैं अगर स्पाउज को लाना चाहूं तो कैसे ला सकता हूं। एक ही जरिया है कि हवाई जहाज से लाऊं। जब मैम्बर रेलवे में स्पाउज को फ्री ले जा सकते हैं तो यह कंसैशन ऐसे मेम्बरों को मिलना चाहिये जिन को हवाई जहाज के सिवाय और कोई रास्ता आने जाने के लिए न हो।

बहुत से और भी प्वाइंट्स है जिन के बारे में सोचा जाना जरूरी है। मौजूदा बिल में डागा साहब ने जो फैसिलिटीज मांगी हैं, वे सरकार को दे देना चाहिये। लेकिन साथ साथ आगे के लिए कोई कम्प्रिहैंसिव बिल इस सिलसिले में लाया जाना चाहिये जिसके लिए काफी गुंजाईश है। यह बहुत जरूरी है।

हाउसिंग, पोस्टल, वाटर, बिजली, कंस्टीट्यूएंसी और सैक्रेटेरियल फैसिलिटीज के वास्ते जो 750 रूपये की मांग की गई है, उसको भी मैं स्पोर्ट करता हूं।

मैं मेम्बर्ज की पेंशन के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। आपने प्रोविजन कर रखा है कि जो मेम्बर पांच साल तक रह जाता है, उसको पेंशन मिलती है। तो वह पेंशन के लिये एन्टाइटिल्ड है। पिछले दिनों आप एक संशोधन लाये थे कि जो सदस्य 5 साल का समय पूरा नहीं करते हैं, पार्लियामेंट पहले डिजाल्व हो जाती है तो आपने उसमें 60 दिन का प्रोवीजन रखा था कि इतने से अगर शार्ट पड़ता हो उनकी भी पेंशन मिलेगी। लेकिन इस देश में दो कांस्टीट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर 5 से लेकर 7 महीने मियाद 5 साल से कम पड़ती है। हालांकि इलैक्शन नामीनेशन पेपर्स हमको सारे देश के साथ ही फाइल करने पड़ते हैं लेकिन चुनाव जुलाई से पहले नहीं होता है। तो उस मसले में आपने नहीं सोचा कि ऐसे हालात में चुने जाने वाले मेम्बरों को पूरी पेन्शन क्यों नहीं मिलनी चाहिए ? उसका क्या होगा ? सरकार को इस पर सोचना चाहिये। छठी लोक सभा ढाई साल रही क्योंकि मुल्क में कुछ ऐसे हालात थे कि पूरे टर्म नहीं चल पायी। इसमें किसी मेम्बर का फाल्ट नहीं था। हालात की वजह से पहले ही डिजाल्व हो गई। इसलिए इन हालात में भी जो मेम्बर इलेक्ट हुए थे उनको भी वही हक मिलना चाहिये जो 5 साल पूरा करने वाले सदस्यों को मिलते हैं। अगर ऐसा प्रोवीजन नहीं किया गया तो उसमें ऐसे मेम्बर्ज का क्या दोष है, मेम्बर को क्यों सजा मिले ? यह एक डिस्क्रीमिनेशन है हालात की वजह से अगर हाउस जल्दी डिजाल्व हो जाता है या इलैक्शन नहीं हो सकता है जैसे हमारे केस में है तो जो फैसिलिटीज आप हासिल करते हैं वह हमें नहीं मिल पाती हैं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिये और एमेंन्डमेंट लाने की जरूरत है।

माननीय डागा जी ने जो बिल रखा है और उस पर जिस तफसील के साथ मेम्बरान ने अपने विचार रखे उसके बाद हमें इस पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। आपने घंटी भी बजा दी, इसीलिए इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। और तकरीर खत्म करता हूं।

ایریا میں اور پہاڑی ایریا میں رہنے والے لوگوں کے پاس ممبرس کو جانا پڑتا ہے - جہاں تک ریلوے پاس کا سمبندھ ہے اسپاؤز کے لئے بھی فری فرسٹ کلاس پاس کی بات اس بل میں کہی گئی ہے یہ ٹھیک بات ہے وہ ملنا چاہئے - لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا - جن کی کانسٹی ٹیوینسی میں ریلوے لائنیں ہی نہیں ہیں - بہت سے ایسے آنریبل ممبرس ہیں جن کے علاقے میں ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے - لیکن بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ریلویز ہی نہیں ہیں - وہاں پر یہ فری ریلوے پاس کی بات بے معنی بن جاتی ہے - فری ریلوے پاس پر آپ بھارت کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں - لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ بھوکے تو نہیں گھوم سکتے ہیں جیب میں بھی کچھ ہونا چاہئے میں سمجھتا ہوں کہ جن کانسٹی ٹیونسیز میں ریل کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں وہاں پر اگر کوئی ممبر دورے پر جاتا ہے - خاص طور پر اپنی کانسٹی ٹیوینسی میں تو اس کے لئے کوئی extra الاؤنس ہونا چاہئے - تاکہ اس کو کچھ کمپنسیشن کیا جا سکے جہاں تک ممبروں کو فری فرسٹ کلاس ریلوے پاس کا سوال ہے ان کو آپ ایئر کنڈیشن میں سفر کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں - جب کہ بھور، کریٹس جیسے

[شری پی - نام گیال (لداخ)]: سبھاپتی جی - محترم ڈاگا صاحب نے سیلری اینڈ الاؤنسز بڑھانے کے بارے میں جو بل پرستوت کیا ہے اس بل کا میں سمرتھن کرتے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں -

جیسا کہ ڈاگا صاحب نے اس ایوان کے سامنے ڈیٹیل میں اس مسئلے کو پوری طرح ابھارا کوئی ٹاپک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جس پر میں اور کچھ کہہ سکوں - لہذا ان باتوں پر میں نہ جاتے ہوئے چند پوائنٹ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جو کہ شاید بہت سارے سدسیوں کے ذہن میں نہیں ہوں گے - خاص طور پر ان علاقوں کے بارے میں جو ٹرائبل ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں یا جو ریگستانی علاقے ہیں - جیسے راجستھان ہے اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں پر کیا کیا مشکلات ممبروں کو بھگتنا پڑتی ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے ڈاگا صاحب نے اپنے بل میں ممبروں کی تنخواہ جو ۵۰۰ روپئے کی بجائے تنخواہ ایک ہزار روپیہ بڑھانے کے لئے اور الاؤنس ۵۱ روپئے کے بجائے ۱۰۱ روپئے کرنے کے لئے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ بھی کم ہوگا - ان حالات کا صحیح ڈھنگ سے جائزہ لیا جائے جن حالات میں ٹرائبل

ڈپٹی سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری سیکریٹری ایئر کنڈیشن میں جا سکتے ہیں - اور کہا یہ جاتا ہے ان کا status کہ ہم سے نیچے ہیں اگر نیچے ہیں تو وہ تو ایئر کنڈیشن میں سفر کریں گے اور ہم فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے - کہا یہ ایک ممبر کی ڈگنٹی below نہیں ہوگا - لہذا آپ کو ایئر کنڈیشن میں ممبرس کو سفر کرنا الاو کرنا چاہئے - اسپاوز کے ریلوے concession کیلئے جو امینڈمینٹ انہوں نے دیا ہے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب سیشن ہوتا ہے تو اسپاوز کو بھی فری فسٹ کلاس ریل میں سفر کی اجازت ہوتی ہے جیسے اب تو لداخ جیسے علاقوں میں تو نومبر کے مہینے سے لے کر چھ سات مہینے کے لئے راستے بند ہو جاتے ہیں - اور میں اگر اسپاوز کو لانا چاہوں تو کیسے لا سکتا ہوں ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہوائی جہاز سے لاؤں جب ممبر ریلوے میں اسپاوز کو فری لے جا سکتے ہیں - تو یہ کنسیشن ایسے ممبروں کو ملنا چاہئے جن کو ہوائی جہاز کے سوائے اور کوئی راستہ آنے جانے کے لئے نہ ہو -

بہت سے اور بھی پروائزنس ہیں جن کے بارے میں سوچا جانا ضروری ہے - موجودہ بل میں ڈاکٹر صاحب نے جو فیسلٹیز مانگی ہیں وہ سرکار کو دے دینا چاہئے - لیکن ساتھ ساتھ آگے کے لئے کوئی comprehensive بل اس سلسلہ میں لایا جانا چاہئے جس کے لئے کافی گنجائش ہے - یہ بہت ضروری ہے -

ہاؤسنگ ہوسٹل واٹر بجلی کانسٹی چیونسی اور سیکریٹریل فیسلیٹیز کے واسطے جو ۷۵۰ روپئے کی مانگ کی گئی ہے اس کو بھی میں سپورٹ کرتا ہوں - میں ممبرز کی پینشن کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں -

آپ نے پروویژن کر رکھا ہے کہ جو ممبر پانچ سال تک رہ جاتا ہے اس کو پینشن ملتی ہے - تو وہ پینشن کے لئے اہل ٹائٹلڈ ہیں پچھلے دنوں آپ ایک سنشودھن لائے تھے کہ جو سدسئے پانچ سال کا سمے پورا نہیں کرتے ہیں - پارلیمنٹ پہلے ڈزولو ہو جاتی ہے تو آپ نے اس میں ساتھ دن کا پروویژن رکھا تھا - کہ اتنے سے اگر شارٹ پڑتا ہو تو اس کو بھی پینشن ملے گی - لیکن اس دیش میں دو کانسٹی چیونسی ایسی ہیں جہاں پر پانچ سے لے کر سات مہینے کی میعاد پانچ سال سے کم پڑتا ہے حالانکہ الیکشن nomination پیپرس ہم کو سارے دیش کے ساتھ ہی فائل کرنے پڑتے ہیں لیکن چناو جولائی سے پہلے نہیں ہوتا ہے تو اس مسئلے

[شری بی - نام گھال]

میں آپ نے نہیں سوچا کہ ایسے حالات میں چلے جانے والے ممبروں کو پوری پینشن کیوں نہیں ملنی چاہئے ؟ کہ اس کا کیا ہوگا سرکار کو اس پر سوچنا چاہئے - چھٹی لوک سبھا ڈھائی سال رہی کیونکہ ملک میں کچھ ایسے حالات تھے کہ پورے ٹرم نہیں چل پائی اس میں کسی ممبر کا فالٹ نہیں تھا حالات کی وجہ سے پہلے ہی ڈزولو ہو گئی اس لئے ان حالات میں جو ممبر الیکٹ ہوئے تھے ان کو بھی وہی حق ملنا چاہئے - جو ٥ سال پورا کرنے والے سدسوں کو ملتے ہیں اگر ایسا پرووژن نہیں کیا گیا تو اس میں ایسے ممبرز کا ہمارا کیا دوش ہے ممبر کو کیوں سزا ملے یہ ایک *discrimination* ہے - حالات کی وجہ سے اگر ہاؤس جلدی ڈزولو ہو جاتا ہے یا الیکشن نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہمارے کیس میں ہے تو جو فیسیلیٹیز آپ حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہیں - ان باتوں کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہئے - اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے -

سمانیئے ڈاگا جی نے جو بل رکھا ہے اور اس پر جس تفصیل کے ساتھ ممبران نے اپنے وچار رکھے اس کے بعد ہمیں اس پر زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے - آپ نے گھنٹی بھی بجا دی اس لئے ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کو سپورٹ کرتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں -]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, श्री डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं । लोक सभा देश की सर्वोच्च संस्था है और उसका महत्व-पूर्ण स्थान है । एक मेम्बर पार्लियामेंट 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कहीं 7 लाख है । लेकिन एक विधान सभा सदस्य केवल 1 लाख लोगों का ही प्रति-निधित्व करता है । अब अगर विधान सभा सदस्यों की सैलरी और उनके अलाउन्सेज एक एम. पी. से अधिक हो तो इस विषमता को कोई भी पसन्द नहीं कर सकता है । प्रान्तों में जिस प्रकार से सेलरीज और अला-उन्सेज हैं, जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या नागालैंड में, इनमें मेम्बरों की सेलरीज और अलाउन्सेज लोक सभा सदस्य से ज्यादा हैं । तो इस प्रकार की स्थिति देश में नहीं होनी चाहिये । मैं यह जानता हूं कि देश बड़ी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है और आर्थिक स्थिति से सबल नहीं है, परन्तु यह भी देखना आवश्यक है कि लोक-सभा सदस्य होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है और उसे वह ईमानदारी से कैसे निभाएं मैंने इस सम्बन्ध में बहुत गहराई से चिन्तन और मनन किया है और मैंने यह पाया है कि 500 रुपये की जो सेलरी है, यह मैम्बर के स्टेटस के माफिक ठीक नहीं है। कोई भी सैलरी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें, एसिस्टेंट सैक्रेटरी, क्लर्कस हैं, उनको या दूसरे जो भी आफिसर्स हैं, उनको मिलने वाली तनख्वाहों के मुकाबले में 500 रुपये की एम. पी. की सैलरी बहुत ही कम है । मैं मानता हूं कि स्थिति को देखते हुए जो 1000 रुपये सैलरी का सुझाव दिया गया है, यह बिल्कुल प्रैक्टीकल है ।

दूसरी बात जो 51 रुपये डेली एलाउन्स की बजाय 101 द. डेली एलाउन्स का सुझाव दिया है, उसको मैं नहीं मानता हूं । अगर सदस्य की तनख्वाह 500 रुपये से

1000 रुपये कर दी जाये तो जनता कभी इसकी आलोचना नहीं करेगी परन्तु आज अगर हमारा एलाउन्स 100 रुपये कर दिया जाये तो क्योंकि किसी भी सैक्रेटरी या चीफ सैक्रेटरी का एलाउन्स 100 रूपये नहीं है, इसकी आलोचना अवश्य की जायेगी । इसलिए अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो 51 रुपये जो डेली एलाउन्स के निर्धारित किये गये हैं, वह बिलकुल ठीक हैं, उन्हें नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि गवर्नमेंट में कहीं भी डेली एलाउन्स 51 रुपये से अधिक नहीं है, इसलिए इसे बिलकुल नहीं बढ़ाना चाहिए ।

मेरा तो यह कहना है कि लोक-सभा के सदस्य अपने क्षेत्रों में बहुत कम जाते हैं । वह अपने क्षेत्रों में न जा कर ज्यादा अपना समय कमेटियों की मीटिंगों में बिताते हैं । मैं चाहता हूं कि रूल्स में इस तरह के परिवर्तन किये जायें कि जो इलैक्टेड कमेटीज हैं, उनकी 10 दिन से ज्यादा सिटिंग्ज न हों और जो नामिनेटिड कमेटीज हैं, उनकी 7 दिन से ज्यादा सिटिंग्ज न हों ताकि यह जो आलोचना होती है कि कमेटियों की मिटिंगें कर के मेम्बर्स ज्यादा अर्जन करते हैं, यह जो चार्ज लगाया जाता है जनता की तरफ से, वह चार्ज बिलकुल सही है । इस तरह से मेम्बर्स अपने क्षेत्र की सेवा नहीं कर सकते हैं

यह बहुत मावश्यक है कि मेम्बर्स को महीने में कम-से-कम 15 दिन अपने क्षेत्र में अवश्य रहना चाहिये और जनता व वोटर्स से सम्पर्क करना चाहिये । इसीलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि 51 रुपये के डेली एलाउन्स को किसी सूरत में नहीं बढ़ाना चाहिये ।

सह-यात्री के बारे में जो सुझाव है कि वह स्पाउज के लिए ही न होकर सह-यात्री होना चाहिये इस बारे में जो सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि अटेंडेंट अगर साथ में नहीं होता है तो सदस्य का कोई परपज उससे सर्व नहीं होता है, अगर वह मेम्बर के साथ ही फर्स्ट क्लास में हो तो उसको सहायक हो सकता है नहीं तो उसे कोई स्हयोग नहीं मिलता है, यह ठीक है । कम्पेनियन को चेंज कर के भले ही कोई भी साथ में हो, अटेंडेंट हो या स्पाउज हो, उसको मेम्बर के साथ फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकार होना चाहिये । इसलिये कम्पेनियन शब्द की जगह सहायक शब्द जोड़ना चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : "कम्पेनियन" वर्ड आलरेडी है ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अगर है, तो मेरा विचार है कि उसके लिए भी फर्स्ट क्लास का प्राविजन होना चाहिए । अगर यह व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो स्पाउज के लिए व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए । उसके बारे में क्या कठिनाइयां हैं ? इस बारे में श्री डागा ने विस्तार से कह दिया है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता ।

जहां तक निर्वाचन-क्षेत्र का सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए मेरा क्षेत्र, और जो मित्र मुझसे पहले बोले हैं, उनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा और विस्तृत है । वहां बहुत कठिनाइयां हैं । डेजर्ट एरिया और हिली एरिया में बहुत कठिनाइयां हैं । उन क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था करनी चाहिए कि एम. पीज. तीन, चार या पांच दिन तक, एक निर्धारित किलोमीटर तक, पूल की जीप का प्रयोग कर सकें और सैंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा दे । इससे संसद्-सदस्य का स्टेटस बनता है । आज कलेक्टर का स्टेटस बनाने के लिए जनता की नजरों में एम. पी. का स्टेटस नहीं है । उसका स्टेटस बनाने के लिए यह अवश्य है कि एम. पीज. को तीन, चार या पांच दिन के लिए जीप के प्रयोग की सुविधा दी जाए ।

जहां तक हाउसिंग फैसिलिटीज का सम्बन्ध है, राजस्थान में, और कई अन्य प्रान्तों में, एम. एल. एज. से किराया नहीं लिया जाता है । इसी तरह एम. पीज. से भी किराया वसूल नहीं करना चाहिये । बिजली की भी सीमा बांध देनी चाहियें कि इससे ज्यादा बिजली का प्रयोग करने पर चार्जिज लगेंगे, जैसे कि टेलीफोन के बारे में व्यवस्था है । टेलीफोन-काल्ज की सीमा को भी कुछ बढ़ाना चाहिए—ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । मेरा इतना बड़ा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

क्षेत्र है। वहां से जितने लोग मेरे यहां आते हैं, मैं उन्हें टेलीफोन करने से मना नहीं कर सकता। हम खुद टेलीफोन करें और अपने मित्रों को न करने दें, यह नहीं हो सकता। काम अधिक बढ़ गया है, इसलिए टेलीफोन-काल्ज की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री डागा के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मुझे दुख है कि मुझे डागा साहब जैसे भले और निर्भीक सांसद के विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। यूं यहां बहुत से लोग अपने आप को वाक-बहादुर कहते हैं। वे किसी को पाखंडी कह सकते हैं और किसी को और बातों से विभूषित कर सकते हैं। मुझे उसपर कोई एतराज नहीं है। वे जो चाहें, कहें। लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूं, वे उन्हें ध्यान से सुनें और उनपर विचार करें।

श्री डागा के विधेयक में तनख्वाह 500 रुपये से बढ़ा कर 800 रुपये और दैनिक भत्ता 51 रुपये से 65 रुपये करने की बात कही गई है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अब तनख्वाह 101 रुपये करने की बात कही गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर 10001 रुपये, तो वह और ज्यादा है।

यह वृद्धि किस आधार पर मांगी जा रही है, यह मैं माननीय सदस्य के विधेयक के उद्देश्य को पढ़ कर बताना चाहता हूं उसमें कहा गया है :—

"निर्वाह-व्यय और मुद्रा स्फीति में बहुमुखी वृद्धि तथा सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण संसद सदस्यों का वेतन, दैनिक भत्ता और अन्य फायदे बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि वे अपने कृत्यों का उचित रूप में निर्वहन कर सकें।"

मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं : क्या महंगाई केवल 750 संसद्-सदस्यों के लिए ही बढ़ी है ? या पूरे हिन्दुस्तान की जनता को इस का मुकाबला करना पड़ रहा है ? कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी मंहगाई है, दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी मंहगाई है और हमारे राज्य सभा और लोक सभा में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी मंहगाई का सवाल है। यह सर्वमुखी सवाल है। तो आप अपनी बात तो कहते हैं लेकिन आज ही सवेरे जब एक प्रश्न पेश था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई की तीन किस्त बकाया पड़ गई, उस को देना चाहिए तो उस पर मंत्री बराबर अगर मगर करते रहे, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस तरह की बात करते रहे। वह तो उन का अधिकार है आप के निर्णय के मुताबिक लेकिन कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जायगी, मंहगाई बढ़ जायगी। इस नाम पर कारखाने में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, बोनस नहीं देंगे, मंहगाई भत्ता नहीं देंगे, दफ्तरों में काम करने वालों को आप इन सहूलियतों से महरूम रखेंगे लेकिन आप शिव जी के त्रिशूल पर रहने वाले साढ़े सात सौ एम० पी० सब से ज्यादा कष्ट में हैं, सब से ज्यादा कष्ट इसी श्रेणी को है जो शीत ताप नियंत्रित इन मकानों रह रही है, उन्हीं के लिए यह मंहगाई ज्यादा बढ़ गई है ? इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आप को उन के लिए भी बोलना चाहिए।

श्री मूल चंद डागा : आप ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वकालत नहीं की ? आप ने एल आइ सी के लिए वकालत नहीं की ?

श्री रामावतार शास्त्री: एल आई सी के कर्मचारियों को तीन हजार नहीं मिलता। आप ने गलत बात कही है। . . . (**व्यवधान**). . . इस तरह से मैं घबड़ाने वाला नहीं हूं। मेरी बात सुनिए। मेरा तीर निशाने पर लग रहा है, इसलिए आप लोग घबड़ा रहे हैं।

आज अगर मंहगाई है तो सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की जनता के लिये है, किसान, मजदूर, आप, हम, सारे लोगों के लिए है। सरकारी कर्मचारी, गैर-सरकारी कर्मचारी, सभी

के लिए है । आज आधी से ज्यादा हमारी आबादी गरीबी की लाइन से नीचे रहती है । उसके लिए तो आप नहीं कभी बोलते कि यह बढ़ाओ । इसीलिए इस आधार पर मैं इस का विरोध करता हूं । आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं है और साथ-साथ जनता की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि आप की इन मांगों का समर्थन आम जनता कर सके । आप ने, हम लोगों ने क्या अपनी अपनी जनता से, अपने वोटरों से इस के बारे में राय ली है? आप राय लिजिए और अगर आपकी जनता यह कह दे, बहुमत तो जरूर ले लीजिए ।

एक माननीय सदस्य : हम ने पूछा है जनता से, फिर आए हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैंने भी पूछा है ... **(व्यवधान)** ...

मैं तो अपनी बात कह रहा हूं । मुझे अभी कुछ और बात कहनी है । मैं यह कह रहा हूं कि आप जनता की राय लीजिये अगर आप सचमुच में यह चाहते हैं । अखबारों में संसद सदस्यों के बारे में उन के खिलाफ कितना लिखा जाता है वह आप पढ़ते हैं, उसके बावजूद इस तरह की बात करते हैं । इसलिए मैं इस सिद्धांत पर इस का विरोध कर रहा हूं कि मंहगाई केवल आप के लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है । पहले उनके लिए इंतजाम कीजिए तब आप अपने लिए इंतजाम कीजिए ।

तब मैं चाहता क्या हूं यह आप पूछ सकते हैं । आप नकद पैसा जो मांग रहे हैं यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए । आप कहेंगे कि हम संसद सदस्य हैं, हमारी जवाबदेही है, उस को पूरा करना हमारा काम है, हमें जनता की सेवा करनी है, उन के बीच में वहां जाना भी है, उन स सम्पर्क भी बनाना है, अगर वह आएं तो उन्हें अपने घरों में रखना भी है, ये सारे काम करने हैं । तो आप सैक्रेटैरियल सहायता मांगिए, आप डाक तार की सहूलियत मांगिए ... **(व्यवधान)** ...

एक माननीय सदस्य : आप नाक यों पकड़ रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, सुनिए । मैं नाक यों नहीं पकड़ रहा हूं । **(व्यवधान)** ये लोग नाक की बात बोलते हैं इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि जो काम नहीं करेगा उसे सैक्रेटैरियल असिस्टेन्स नहीं मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसे डाक तार विभाग की सुविधा नहीं मिलेगी और जो काम नहीं करेगा उसे ज्यादा टेलीफोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इस तरह से कम से कम उन पर तो सरकार का पैसा बचेगा । इसीलिए मैं नकद के खिलाफ हूं । जो भी काम करेंगे अपने क्षेत्र का, अपने देश का उनको जरूर इन सुविधाओं का अधिकार होना चाहिए । **(व्यवधान)** इसलिए आप सेक्रेटेरियल सहायता दीजिए, टेलीफोन की सुविधा दीजिए, डाक-तार की सहूलियत दीजिए । चिट्ठियां भेजने की सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि आज कार्ड के दाम बहुत बढ़ गए हैं । एक साधारण बधायी-पत्र जो पहले 40 पैसे में मिलता था उसका दाम 75 पैसे हो गया है और जो रंगीन बधायी-पत्र 55 पैसे में पहले आता था वह 75 पैसे का हो गया है। आप कहिए कि इनके दाम नहीं बढ़ाए जायें ।

जहां तक क्षेत्रों में घूमने का सम्बन्ध है हमें कम से कम दो महीने के लिए जीप मिलनी चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्र का दौरा कर सकें । यह सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए, रुपया नहीं मिलना चाहिए। जनता के ऊपर इसका कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा और जो लोग काम करेंगे उन्हीं को यह सहूलियत मिल सकेगी ।

आपने यह कहा कि मेरी बीबी को पूरे देश का बादशाह बना दिया जाए घूमने के लिए ।आप इसकी मांग क्यों करते हैं ? अभी जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत वे सेशन में दिल्ली आयेंगी और सेशन के बाद जायेंगी लेकिन हमने देखा है कि कितने ही सदस्य कई दफा लाते हैं और ले जाते हैं जोकि गलत है लेकिन ऐसा हो रहा है । इसको आप खत्म करें या फिर इजाजत दीजिए कि पत्नियों को, स्पाउज को, या कोई विधुर है विधवा है तो किसी और को, अगर चाहें तो कई दफा दिल्ली ला सकें । आप

[श्री रामावतार शास्त्री]

इस बात की मांग कीजिए लेकिन पूरे देश की बात आप मत कीजिए ।

इसी तरह से आज हम हवाई अड्डा जाते हैं तो 25-30 रुपया देना पड़ता है जबकि 13 किलोमीटर के लिए 13 रुपये ही मिलते हैं । अगर इसका रेट बढ़ाया जाता है तो ठीक होगा लेकिन तनख्वाह बढ़ाई जाए और भत्ते बढ़ाए जायें--यह बात गलत है । इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा आप जो एफीशिएन्सी बढ़ाने की बात करते हैं तो एफीशिएन्सी बढ़ाने वाली चीजें मांगिए, नगदनारायण की मांग मत कीजिए । नगदनारायण अधिक देने की स्थिति में आज यह देश नहीं है । इसलिए आपने जो पैसे की मांग मत कीजिए । नगदनारायण अधिक देने की स्थिति में आज यह देश नहीं है । इसीलिए आपने जो पैसे की मांग की है उसका मैं विरोध करता हूं । मैं समझता हूं डागा साहब इस विधेयक को विड्ड्रा कर लेंगे और इसकी जगह पर कोई दूसरा बिल उस प्रकार का लायेंगे तो उस पर हम विचार कर सकते हैं, वह उचित भी होगा और उचित समझा भी जायेगा । इस बिल को आज जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : शास्त्री जी का कहना है कि एक हजार रुपया मत दो, दो हजार की फैसिलिटी दे दो ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, डागा जी ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं इस सदन के दोनों पक्षों ने इसका समर्थन किया है---कुछ लोगों ने स्पष्ट तौर पर किया है तो शास्त्री जी जैसे कुछ लोगों ने इधर से घुमाकर नाक पकड़ने की चेष्टा की है । मंशा उनकी भी यही है कि सदस्यों को सुविधायें मिलनी चाहिए । मेरा माननीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में और ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं है । संसद यदि ठीक से अपनी ड्यूटी न कर पाये और उनकी ड्यूटी के निर्वहन में सुविधायें कम होने से कुछ बाधा पैदा होती हो तो मैं समझता हूं कि उससे राष्ट्र का नुक्सान हो रहा है । इसके साथ मैं माननीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग अपनी कान्स्टीचुयेंसीज में जाते हैं तो वहां जिला अधिकारी से कहें कि हमको कम से कम महीने में दस दिन जीप या कार उपलब्ध करायें ताकि हम अपनी कास्टीचुयेंसी में भ्रमण कर सकें, लेकिन वह सब फ्री-आफ-कास्ट होना चाहिए ।

इसी प्रकार सचिवालय का जहां तक सवाल है, उसमें हमें एक स्टैनो मिलना चाहिए और इसके साथ यदि पोस्टल खर्च के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वह हमको वहन न करना पड़े ।

जहां तक टेलीफोन का सवाल है, उसमें यह होता है कि 15 हजार काल के बाद, जब वह टेलीफोन करेगा तो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा । इसलिए जब हम अपनी सैलरी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि उसका अधिकांश पैसा तो टेलीफोन पर खर्च हो गया है । यह स्थिति दोनों, एस.टी.डी. और साधारण पर लागू होती है । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 15 हजार काल के स्थान पर 25 हजार काल कर दीजिए । इसके अतिरिक्त आने जाने के व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए अपना भाषण समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में हकीकत को देखते हुए वे इस बिल को स्वीकार कर लें ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, डागा जी ने जो बिल सदन में रखा है, वह बहुत मौके से रखा है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं । बाकी शास्त्री जी कहते हैं कि गरीबों का ख्याल रखना चाहिये, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं इलैक्शन में गांव में गया था, वहां जाकर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, वह कर दूंगा । 1966 में जब मैं सदस्य बना, मैं गरीबों को मदद तो करता रहा हूं, वे मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब पहले आप अपना मकान तो बना लो, तुम्हारी कार कहां है, यदि पैसा चाहिए तो हम से ले लो, तो यह तो लोगों की हालत है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मिनिस्टर था, तो मेरे पास कार थी, उसके बाद मैं उसको

एफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने पूछा तो कहने लगे कि कार मत बेचना, अगर थैला लेकर जाओगे तो कुत्ते पीछे पड़ेंगे और कार लेकर जाओगे तो लोग मिलेंगे। जनता किसकी बात मानती है, उसकी बात मानती है जिनके पास पैसा होता है। अपना मसला तो हम हल नहीं कर सकते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे। यह कहते हैं मजदूरों का करेंगे, किसानों का करेंगे, व्यापारियों का करेंगे, किसानों का करेंगे, लेकिन अपना तो कर नहीं सकते हैं, तो दूसरों का क्या करेंगे। आप लिख कर दे दो, तो सत कुछ हो जाये, लेकिन इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा और उस सूरत में आप दूसरों के लिए क्या कर सकेंगे। जो खुद भूखा है वह मजदूरों के लिए क्या करेगा ? चैरिटी-बिगिन्ज-एट-होम। सब महात्मा गांधी नहीं बन गये हैं, इस तरह से सोचना गलत बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीधी बात करो, घुमा-फिराकर कहने से कोई फायदा नहीं है। साफ कहो कि हमें यह चाहिये और उसको हासिल करो।

Nobody can get his right by request, rights are wrested from unwilling hands.

आप कहते हैं--टेलीफोन के लिए दो, बिजली के लिए दो, मैं कहता हूं सीधे क्यों नहीं मांगते हैं, कानों को सीधे हाथ लगाओ, घुमा कर हाथ लगाने से क्या फायदा है। ठीक है, दुनिया में लोगों का ज्यादा मिलता होगा, हम ने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, हमें जिस चीज की जरूरत है वह हमें मिलनी चाहिए।

हम को कांस्टीचूएन्सी में जाना होता है। अभी एक मेम्बर साहब ने कहा कि 10 दिन के लिए कार दे दो। इस तरह कार लेने से क्या फायदा, कार देनी है तो इन्टरेस्ट-फ्री लोन दो जिस से हम कार खरीद सकें और उसके चलाने पर माइलेज दिया जाना चाहिये। हमारे यहां पंजाब में शायद सवा रुपये फी किलोमीटर दिया जाता है, आप एक रुपया फी किलोमीटर दे दो। मैं चण्डीगढ़ जाता हूं, कार में चाहता हूं, मेरी तनख्वाह 500 रुपये है, जो सब उस जाने--आने में खर्च हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। जब मैं स्टेट में मिनिस्टर था कार इस्तेमाल करता था, जब मेम्बर था तब भी कार इस्तेमाल करता था क्योंकि उसका पैसा मिलता था। कार में क्यों जाते हैं? इस लिए जाते हैं कि रास्ते में हमें 100 जगह जाना होता है, मैं हरियाणा भी जाता हूं, चण्डीगढ़ भी जाता हूं, पंजाब भी जाता हूं, लोगों से मिलना होता है, दस तरह के काम करने होते हैं। इसलिए इन्टरेस्ट-फ्री लोन मिलना चाहिये और किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्च मिलना चाहिये।

अब मैं टेलीफोन की बात बतलाता हूं--जब मैं नया-नया यहां आया और मुझे टेलीफोन मिला तो उस में एस. टी. डी. लगा हुआ था। लोगों ने खूब टेलिफोन किये। जब मैं तनख्वाह लेने गया तो मुझे कहा गया कि चौधरी साहब, आप का तो कुछ नहीं बचता सब टेलीफोन में निकल गया। मैंने कहा, चलो अगले महीने देख लेंगे, लेकिन अगले महीने भी कुछ नहीं मिला। . . . (**व्यवधान**) . . . शास्त्री जी, आप ने अपनी स्पीच में क्या कहा है, जरा साफ-साफ बात करो। जो खुद भूखा है वह दूसरों को क्या खिलायेगा, दूसरों को क्या देगा।

डागा साहब ने जो संशोधन दिये हैं वे बिल कुल ठीक है, उन को जरूर मान लेना चाहिये। क्या 65 रुपये रोज का भत्ता ज्यादा है, मैं कहता हूं--100 रुपये रोज होना चाहिये। आप देखिये-- हम टैक्सी पर जाते हैं कितना पैसा लग जाता है, कभी-कभी तो 100 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ता है। अगर कोई एम. एल. ए. कारखाना लगा लेता है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, कोई भी काम करना चाहे तो लोग नहीं छोड़ते हैं, ऐसी हालत में वह क्या करेगा। उस के पास पैसा नहीं है, आप उसे काम करने देना नहीं चाहते, रिश्वत लेने नहीं देते, ऐसी हालत में वह कैसे ईमानादार रह सकता है। इस लिए पहले अपने घर को देखो, तब आप दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। आप कहते हैं कि हम मजदूरों से बात नहीं करते, मजदूरों को तो आप खुद एक्सप्लाएट कर रहे हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है हम तो खुद मजदूरी करते हैं। जब मैं मिनिस्टर

[श्री सुन्दर सिंह]

था, मैं उस वक्त भी खेती-बाड़ी करता था। मैं आप को बता दूं कि यह कोई आप की क्वालीफिकेशन नहीं है । तुम सारी उम्र नहीं होते। वे कहते हैं कि तुम सारी उम्र मेम्बर बने रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई अच्छा जूता नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं हैं । आप क्या बात करते हो । आप ने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे लिए क्या करोगे । इसलिए मैं कहता हूं कि जो खाने-पीने वाले लोग हैं, उन को वे वोट देते हैं। काम करने वाले और गरीब आदमी पर तो जूते पड़ते हैं । आप खड़े कर के देख लो किसी गरीब आदमी को? जिस के पास वह वोट लेने के लिए जाएगा, वह यही कहेगा कि यह खुद भूखा है, तो हमें क्या देगा । यह प्रक्टिकल बात है और इस को मान लेना चाहिए। मैं पूछता हूं कि आप ने अपनी तनख्वाह लोगों को बांटी है।

श्री रामावतार शास्त्री : बांटी है ।

श्री सुन्दर सिंह : छोड़ो शास्त्री जी, यह क्या बात है। शास्त्री जी, मैं कहता हूं कि आप को तो हमेशा भूखे मरते रहना है, कुछ हमें तो दो। इसलिए छोड़ दो इस बात को , इस से कोई काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा कि जो सहूलियतें डागा साहब ने रखी हैं, उन सब को मान लेना चाहिए।

यह जो टैलिफोन है, यह एक स्यापा है हमारे लिए। इस की हमेशा फिक्र रहती है। मैं ताला लगाकर जाता हूं और कोई आदमी काल करने के लिए अगर आता है, तो मैं करने नहीं देता । कुछ लोग तार लगा कर फिर भी टेलीफोन कर जाते हैं । यह भी मुझे भरना पड़ता है । अब मैं कहां से पैसा लाऊं। इसलिए टैलिफोन के बारे में भी कुछ सहूलियतें हमें और मिलनी चाहिएं।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कार का एलाउन्स हमें मिलना चाहिए और कार खरीदने के लिए इन्ट्रेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए । इसी तरह से कोठी के लिए इन्ट्रेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए ताकि कोई जगह रहने के लिए बना सके क्योंकि मैम्बर हमेशा तो कोई बना नहीं रहेगा । हम तो शुरू से ही मैम्बर रहे हैं लेकिन कोई आदमी पांच साल रहता है और उस के बाद मैम्बर नहीं बन पाता। इसलिए वह मकान बना ले ताकि उस को आगे दिक्कत न उठानी पड़े।

फिर जो पैंशन एम.एल.ए. को मिलती है, वही आप को भी मिलती है । उस में कोई गिला नहीं है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को एक रुपया फी किलोमीटर एलाउन्स मिलना चाहिए, अगर आप को कार नहीं देनी है । अगर स्टेट गवर्नमेंट निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए कार नहीं देती है, तो कम से कम इतना एलाउन्स तो मिलना चाहिए । मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जाता हूं और सेशन के दौरान भी जाता हूं, तो कार से ही जाता हूं । गुरदासपुर अगर जाता हूं तो 200 रुपये खर्च होते हैं, फिर वापस आ कर चंडीगढ़ गया तो 200 रुपये और खर्च किये और फिर कार से वापस आने पर 200-200 रुपये और खर्च हो जाते हैं ।इस तरह से एक दफा में 800 रुपये खर्च हो जाते हैं। मैं हमेशा कार से ही जाता हूं । इसलिए यह मेहरबानी आप मेरे लिए ही कर दें। एक रुपया फी किलोमिटर मेरे लिये कर दो। मैं देख लूंगा कि कौन वोट नहीं डालता । मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, सारा सिलसिला कर दो, फिर मैं देखूंगा कि कौन वोट नहीं डालता। लोग खुशी से वोट डालेंगे । आप भी खाओगे और लोगों को भी खिलाओगे। मजदूरों के लिए कौन नहीं कर रहा है । मजदूर ही हम को कहते हैं कि तुम कैसे चौधरी हो, सारी उम्र क्या करते रहे, न कोठी है और न कार है। यह वे लोग कहते हैं, जिन की दुहाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आप चौधरी साहब, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी कोठी में रहो और तुम से न हो सके, तो हम से ले लो । इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह आप की डिस्क्वालीफिकेशन है, यह क्वालीफिकेशन नहीं है । बिजली की यह बात है कि बिजली वालों को बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का पैसा देना पड़ता है, टेलीफोन का पैसा

देना पड़ता है और कार का पैसा देना पड़ता है आप जो यह कहते हैं कि लोगों से पूछ लिया, मैंने तो लोगों से पूछ लिया है। वे तो कहते हैं कि चौधरी साहब खूब खाओ खूब कमाओ। मेरे वोटर तो मुझे कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी हालत अच्छी होनी चाहिए, आप सारी उम्र मेम्बर रहे हैं, अब भी क्या आप उसी हालत में रहेंगे।

इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप यह देवतापन छोड़ दो। आपने जो यह ढंग अपना रखा है इसलिए लोगों का काम नहीं बनता है। मैं कहता हूं कि पहले अपनी सेहत ठीक करो, फिर गरीबों की बात करो। यह सारी दुनिया की बात है। खाली लिप सिम्पैथी से गरीबों का मसला हल होने वाला नहीं है। उनके लिए सिम्पैथी दिखाना गलत बात है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आप से कहता हूं कि जो कुछ आपका बढ़े वह आप हमें दे देना। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ी तो वह हमें दे देना।

मैं इस के बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो हमें 51 रुपये रोज मिलते हैं ये बहुत कम हैं। ये सौ रुपये रोज होने चाहिएं। यह जो हमें तनख्वाह मिलती वह भी बहुत कम है। यह भी बढ़नी चाहिए। मेरी कांसटिच्युन्सी में कोई मुझे इसके बारे में कहने वाला नहीं है। उन्हें इस से कुछ मतलब नहीं कि मुझे क्या मिलता है। मेरे वोटर तो चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिएं।

मैं डागा साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वे यह बिल लाए। इससे मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कार के लिए हमें इन्ट्रेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए। अब डीजल इंजन की एम्बेसडर कार 98 हजार रुपये की आती है। उसके लिए बैंक वाले 18 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट मांगते हैं। हमारे पंजाब में कार और मकान के लिए लोन पर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। यहां पर क्यों इन्ट्रेस्ट हो? मैं आप से कहता हूं कि आप एम. पी. हो कर अपना मसला हल नहीं कर सकते। जो अपना मसला हल नहीं कर सकता वह दूसरों का मसला कैसे हल कर सकता है। सब से पहले हमें अपना मसला हल करना चाहिए। अगर हमारा दिमाग और सेहत बनी रहेगी तभी हम दूसरों का मसला भी हल कर सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इससे हमें लोग सेल्फिश कहेंगे।

श्री सुन्दर सिंह : मेरे वोटर मुझ को सेल्फिश नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं डागा साहब के बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : इसके लिए समय बढ़ा दिया जाए, काफी मेम्बर बोलने वाले हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): कम से कम दो घंटे का समय बढ़ाया जाए। ज्यादा से ज्यादा मेम्बरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to extend the time by two hours more.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, we have extended the time by two hours more. Mr. Yadav.

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : सभापति जी, तनख्वाह बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, एक सदस्य को मिलना चाहिए-- दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि मौलिक सवाल यह नहीं है। मौलिक सवाल यह है कि इस देश के लोकसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के उत्तरदायित्व क्या हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए किन-किन साधनों की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि हमारे सामने ये दो ही मुद्दे हैं और यह जो तनख्वाह बढ़ाने की बात कही गई है, डागा साहब ने बहुत भयभीत होकर 65 रुपये या 100 रुपये करने की बात कही है। सभापति जी, मैं 6 वर्ष तक मंत्री रहा। उस समय 1480

[श्री डी. पी. यादव]

रुपये तनख्वाह मिलती थी और गाड़ी मिलती थी, पीछे पुलिस वाहन रहता था और जहां भी जाओ वहां पर सलामी मिलती थी । उस समय शायद अनुभव न हुआ हो, लेकिन सभापति जी जो व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, मंत्री पद छोड़ने के बाद उसे अवश्य महसूस होता है । इस सदन में भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, जो पद से हटने के बाद भिखारियों की तरह घूमते रहे हैं और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है ।

हमारे यहां यह हालत है कि कभी मोटर पर बैठ जाओ तो कहते हैं कि बड़ा चोर है और पैदल जाओ तो कहेंगे कि देखो भिखमंगों की तरह चला आया है । इस तरह तानों को सुनना पड़ता है तो इस तरह से देश का निर्माण नहीं हो सकता ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वेंकटसुब्बैया साहब यहां पर बैठे हैं । 18-19 सौ रुपये इनको तनख्वाह मिलती होगी । अगर किसी मंत्री को ईमानदारी से अपने परिवार को चलाना है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना है तो मैम्बर्स की तनख्वाह बढ़ाने से पहले मैं मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगा । पहले मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाओ ।

एक चीज मैं और बतला दूं कि इस देश में मंत्री का पद राष्ट्रपति से बड़ा है । आप कहेंगे कि कैसे ? शोभा के लिए भले ही राष्ट्रपति का पद बड़ा हो, लेकिन एक्शन के लिए डिप्टी मिनिस्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है । मैं डिप्टी मिनिस्टर था तो मेरे पास करोड़ों रुपये का डिस्बर्समेंट पावर था । चाहे दो करोड़ इधर कर दो या 10 करोड़ उधर कर दो, वही आदमी कल भिखमंगा बनेगा, इस की चिंता जब उसको होती है तो वह भी यह सोचता है कि इसी में से कुछ रख लो--भविष्य में जो होगा देखा जाएगा । इस स्थिति से इस देश के प्रजातन्त्र को बचाओ ।

सभापति महोदय, आप चुनाव क्यों करवाते हैं । चुनाव का क्या प्रयोजन है । मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोकसभा का चुनाव प्रधान मंत्री का चुनाव करने के लिए होता है और विधान सभा का चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए होता है । प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसा चाहें अपना मंत्रिमण्डल बना लें और फिर आप चाहे जितनी बक-बक करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होता । जो आफिसर चाहते हैं वही निर्णय होते हैं । 14 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला जो कुछ कहे, उसका कोई महत्व नहीं और एक बी. डी. ओ. जो कह दे, उसका महत्व होता है । एक बी. डी. ओ. के पावर्स और रेस्पांसीबिलिटी ज्यादा है । आप इन सब चीजों को देखने की कोशिश कीजिए । एक बी. डी. ओ. की पावर्स ज्यादा है, एक दरोगा के पावर्स ज्यादा हैं, एक इंस्पेक्टर के पावर्स ज्यादा हैं, लेकिन एक लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य के पास कोई पावर्स नहीं हैं ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav, would you finish within five minutes or would you take some time more?

SHRI D. P. YADAV: I will take some more time.

MR. CHAIRMAN: Then you can continue next time.

The House now stands adjourned till 11 a. m. on the 30th November, 1981.

17—59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 30, 1981/Agrahayana 9, 1093 (Saka).

GMGIPND— M— 2491 L. S.